WWW.Kanchanujala.in

हिन्दी दैनिक

kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

लखनऊ से प्रकाशित

सच्चाई के साथ

वर्षः 01 अंक : 282 | लखनऊ, गुरुवार, 01 अक्टूबर, 2020 | पृष्ठ- 6 | मूल्य - 1 रुपये

अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया वूट सेलेक्ट की नई वेब सीरीज़ का टीज़र

बाबरी विध्वंस में आसामाजिक तत्वों का हाथ, सभी 32 आरोपी बरी

लखनऊ, संवाददाता। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी केस मस्जिद विध्वंस मामले में आज बुधवार को फैसला आ गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि अदालत ने साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया. उन्होंने साथ ही कहा कि अब इस मामले को उच्च न्यायालय

में ले जाया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मामले में आए फैसले को मजाक बताया है. उन्होंन ट्वीट कर कहा कि यह न्याय का मजाक है. बाबरी मस्जिद के विध्वंस का आपराधिक अभियोग जिन लोगों पर था वे सब बरी हो गए. एक मस्जिद खुद गिर गई? उस समय की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने इसे कानून का भयावह उल्लंघन बताया था. अब ये फैसला! शर्मनाक. वहीं एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने एक शेर ट्वीट किया है -वही कातिल, वही मुंसिफ अदालत उस की. वो शाहिद बहुत से फैसलों में, अब तरफदारी भी होती है। लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई, उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया है, वो काफी अहम है. हम सभी के लिए खुशी का पल है. आडवाणी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद अच्छा समाचार मिला है, बस इतना ही कहूंगा कि जय श्री राम. बुधवार को फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने उनके घर के बाहर इकट्ठे हुए समर्थकों के लिए मिठाई भी बंटवाई. बीजेपी नेता ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और वकीलों का शुक्रिया अदा किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने के बाद साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि धर्म के काम में बड़ी बाधाएं आती हैं लेकिन ईश्वर सत्य के साथ होता है. न्याय हुआ है, हमें

आज का दिन खुशी का: आडवाणी

नयी दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के आरोपियों ने इस मामले पर बुधवार को आये फैसले पर खुशी व्यक्त की है। इस मामले के आरोपी पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा कि आज का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हम सब के लिए खुशी का दिन है। लम्बे समय के बाद अच्छा समाचार आया है। हमने जय श्री राम कह कर इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह हृदय से इस फैसले का स्वागत करते हैं।

खुशी है कि अदालत ने धर्म के कार्य को सही माना है.आरोप के कलंक से मुक्त हो गए. आज सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया- लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री कल्याण सिंह, डा. मुरली मनोहर जोशी, उमाजी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं. इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी के वकील विमल श्रीवास्तव ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, साक्ष्य इतने नहीं थे कि कोई आरोप साबित हो सके। अयोध्या जन्मभूमि मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले मुसलमान हैं. अच्छा है, अगर अदालत ने बरी कर दिया तो ठीक है, बहुत लंबे समय से अटका हुआ मामला था, खत्म हो गया, अच्छा हुआ, यह ठीक है हम तो चाहते थे कि पहले ही इसका फैसला हो जाए। बचाव के पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की तरफसे जो दलील पेश किए गए उसमें मेरिट नहीं थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से जो साक्ष्य पेश किए वो दोषपूर्ण थे और उस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने माना की श्रद्धालुओं को कारसेवक मानना सही नहीं थी. सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा उनमें और आरोपियों के बीच किसी तरह की सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली

बाबरी फैसले पर ओवैसी ने खड़े किए सवाल, पूछा- क्या जादू से गिरी मस्जिद?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद पर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज के दिन को अदालत की तारीख का काला दिन बताते हुए पूछा है कि क्या मस्जिद जादू से गिर गई थी? फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी, शिवसेना, वीएचपी, कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दिन (6 दिसम्बर, 1992) मस्जिद कोई जादू से गिर गई थी?

कोरोना के 80 हजार नये मामले 86 हजार से अधिक हुए स्वस्थ

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 80,472 नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख के पार पहुंच गया हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 86 हजार से अधिक लोगों ने कोरोना संक्रमण को भी मात दी जिससे सक्रिय मामले सात हजार से अधिक घट गये। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों की कुल संख्या अब 62,25,764 हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 86,428 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 51,87,826 हो गयी है। संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामलों की संख्या में 7,135 की कमी आयी है और अब यह 9,40,441 रह गयी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,179 मरीजों की मौत हो गयी जिससे संक्रमण से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 97,497 हो गयी है। देश में सक्रिय मामले 15.11 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.57 फीसदी रह गये हैं जबकि रोगमुक्त होने वालों की दर 83.33 प्रतिशत हो गयी है। कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 4,666 कम होकर 2,60,789 रह गये हैं जबकि 430 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 36,181 हो गयी है। इस दौरान 19,212 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 10,69,159 हो गयी। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 3,689 की वृद्धि हुई है और राज्य में अब 1,07,756 सक्रिय मामले हैं।

शुभकामनाओं के लिए नायडू ने जताया आभार

नयी दिल्ली, एजेंसी। उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य लाभ के लिए मिली शुभकामनाओं के प्रति आभार प्रकट किया है और कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। श्री नायडू ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि वह सभी सावधानियां बरत रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए स्नेही देशवासियों, मित्रों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तथा विधायक-सांसदों की शुभकामनाएं पा कर अभिभूत हूं। मैं ठीक-ठाक हूं और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सभी उपचार और सावधानियां बरत रहा हूं। आप सब की शुभेक्षा से चिंता की कोई बात नहीं है। श्री नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कल देर रात इसकी स्वयं जानकारी दी। उप राष्ट्रपति को स्वास्थ्य लाभ के लिए देश विदेश से शुभकामनायें मिल रही है।

प्रदेश में अब तक 01 करोड़ से अधिक कोविड 19 के टेस्ट हुए जो एक रिकॉर्डः मुख्यमंत्री

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 01 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट हो गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे, सर्विलांस तथा मेडिकल टेस्टिंग की कार्यवाही को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कोविड-19 के खिलाफ पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने तथा रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों

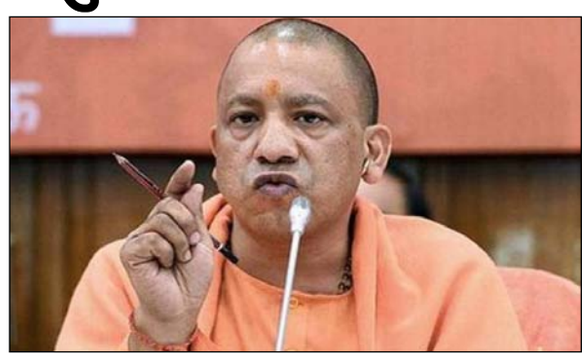

में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता से कार्यशील रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से जनपद स्तर पर संवाद के साथ-साथ सी0एम0 हेल्प लाइन के माध्यम से भी संवाद स्थापित रखा जाए। उन्होंने स्वच्छता तथा सेनिटाइजेशन के कार्यों को लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विलांस कार्यों की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाए। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि सर्विलांस गतिविधियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए। उन्होंने कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड चिकित्सालयों में दवाओं तथा ऑक्सीजन की बैकअप सहित पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। कोविड चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 01 अक्टूबर से प्रदेश में एम0एस0पी0 के तहत धान की खरीद प्रारम्भ होगी। धान क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएं। ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय तथा ग्राम सचिवालय का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हाथरस की घटना की जांच के लिए 03 सदस्यीय एसआईटी गठित की

हाथरस की घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगाःमुख्यमंत्री

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस की घटना की जांच हेतु 03 सदस्यीय एस0आई0टी0 गठित की है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित एस0आई0टी0 में पुलिस उपमहानिरीक्षक चन्द्र प्रकाश तथा पूनम, सेना नायक पी0ए0सी0 आगरा सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री जी ने एस0आई0टी0 को अपनी रिपोर्ट 07 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से वार्ता की और दोषियों के खिलाफकठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमन्त्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाथरस की घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर तथा प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जायेगी।

पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के अधिकारियों ने बुधवार को डब्ल्यूएमसीसी की बैठक की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से हुई इस बैठक में एलएसी पर जारी मौजूदा हालात को लेकर समीक्षा की गई और तनाव घटाने के उपायों पर चर्चा की गई। बीते 20 अगस्त को भी बैठक हुई थी। मौजूदा बैठक में इसके बाद पैदा हुआ घटनाक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक में हुई बातचीत के बारे में बताया कि दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि कमांडर स्तर की बातचीत को बढ़ावा देने की जरूरत है। दोनों देशों ने कमांडर स्तर के अगले दौर की बातचीत के लिए भी सहमत हुए। मौजूदा वार्ता में पूर्वी लद्दाख में करीब पांच महीने से जारी सीमा गतिरोध दूर करने के लिए पांच सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर गौर किया गया। मालूम हो कि बीते 10 सितंबर को मास्को

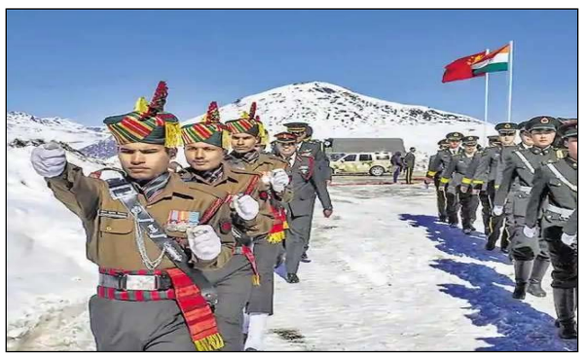

में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हुई थी। इसमें तनाव घटाने के लिए पांच सूत्री फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। रूस में विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों देश जिस पांच सूत्री फॉर्मूले पर सहमत हुए थे उनमें सैनिकों को शीघ्रता से पीछे हटाना, तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों से दूर रहना, सीमा प्रबंधन पर सभी समझौतों एवं प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल है। यही नहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति बहाल करने के अन्य जरूरी उपाय करना भी इस फॉर्मूले में शामिल है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि चीन तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एनलाई द्वारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सात नवंबर 1959 के एक पत्र में प्रस्ताव किए गए एलएसी का पालन करता है।

खेतों में पराली को खाद बनाएगी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के सभी किसानों के खेतों में पराली को खाद बनाने के लिए दिल्ली सरकार फ्री में पूसा इंस्टिट्यूट की तरफ से बनाए गए घोल का छिड़काव करेगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि घोल डालने के 15-20 दिन बाद पराली के डंठल गल जाएंगे और खाद बनने लगेंगे। इसके लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने बताया कि 5 अक्टूबर से घोल बनाना शुरु कर दिया जाएगा और 12 या 13 अक्टूबर तक यह तैयार हो जाएगा। दिल्ली में करीब 800 हेक्टेयर जमीन है जहां पर गैर बासमती चावल की होती बुआई होती है। वहां इसे किसानों की सहमति से छिड़काव किया जाएगा। इस दौरान किसानों का कोई खर्चा नही होगा। घोल के छिड़काव में करीब 20 लाख रुपये की लागत का आएगी जिसे दिल्ली सरकार वहन करेगी। ट्रैक्टर भी सरकार किराए पर लेगी।

यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण देर से आयोजित हो रही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा को चार अक्टूबर से और आगे बढ़ाने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आयोग की ओर से दी गयी दलीलों पर भरोसा जताते हुए यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा के 20 उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। आयोग ने दलील दी थी कि अब परीक्षा टालने का असर अगले साल की परीक्षा पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं इस परीक्षा के आयोजन की सारी तैयारियों की जा चुकी हैं और अब इसे यदि टाला गया तो आयोग को करोड़ों रुपये की चपत लगेगी। आयोग की ओर से कहा गया कि परीक्षा उम्मीदवारों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सभी उचित उपाय किये गये हैं। खंडपीठ ने कहा कि हाल के दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन इस बात का प्रमाण है कि इन परीक्षाओं के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया। न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस से संक्रमित उम्मीदवारों को किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया जायेगा, क्योंकि इससे दूसरे उम्मीदवारों तक वायरस का संक्रमण पहुंच सकता है। न्यायालय ने कहा कि इस साल की परीक्षा को अगले साल की परीक्षा के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कराना संभव नहीं है।

पीएसयू का लाभ बढ़ाने पर जोर दे रही है सरकार: जावडेकर

नयी दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) का कुल कारोबार, कुशलता और लाभ बढ़ाने पर जोर दे रही है। श्री जावडेकर ने यहाँ कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान पीएसयू के कामकाज का ब्यौरा देने वाली पुस्तिका 'आत्मनिर्भर, स्व-पुनर्जीवित और लचीले भारत' का लोकार्पण करते हुए कहा कि जैसे-जैसे देश 'अनलॉक' हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे पीएसयू की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पीएसयू ने 90 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि पीएसयू राष्ट्र का गौरव हैं और मोदी सरकार इन इकाइयों की दक्षता, कारोबार और लाभप्रदता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस अवसर पर राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये सकल लाभ और 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना कारोबार वाले कुल 249 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम परिचालन में हैं। ये लाभांश, ब्याज, कर और जीएसटी के रूप में लगभग 3.62 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करते हैं। इनका सालाना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय लगभग 3,500 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान बिजली की आपूर्ति 99 प्रतिशत रही, लोगों की सेवा के लिए लगभग 24 हजार एलपीजी वितरक, 71 हजार खुदरा आउटलेट, 6,500 डीलर लगातार काम करते रहे।

ओम बिरला के पिता श्रीकृष्ण बिरला का अंतिम संस्कार

कोटा, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्रीकृष्ण बिरला का आज सुबह यहां अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्रीकृष्ण बिरला की अंतिम यात्रा दादा बाड़ी से शुरु हुई और किशोरपुरा मुक्तिधाम पहुंची जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें उनके पुत्र राजेश बिरला और ओम बिरला ने मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार में पूर्व मंत्री, विधायक एवं भारतीय जनत पार्टी (भाजपा) के कई नेता तथा अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके सभी लोगों ने कोरोना के चलते मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। उनके निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया हैं। श्री मिश्र ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके परिजनों को सम्बल प्रदान करने की प्रार्थना की। श्री गहलोत ने श्रीकृष्ण बिरला के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से योगी ने की बात

25 लाख रुपए, घर और नौकरी का ऐलान

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बुधवार शाम को हुई बातचीत में सीएम योगी ने न्याय का भरोसा दिलाया। आज सुबह ही पीएम मोदी ने भी इस मामले पर सीएम योगी से बात कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपए की मदद, घर और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। गैंगरेप पीड़िता की मौत और देर रात को हुए अंतिम संस्कार को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं राज्य की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। देर रात हुए अंतिम संस्कार को लेकर विपक्ष का कहना है कि पुलिस ने साक्ष्य को मिटाने के लिए परिजनों की गैरमौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पुलिस और प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि मंगलवार सुबह पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। देर रात पोस्टमार्टम के बाद जब शव पहुंचा तो परिवार वालों की सहमति से और उनकी उपस्थिति में अंतिम संस्कार कराया गया था। प्रशांत कुमार ने काह कि कुछ महिलाओं द्वारा आरोप लगाए हए हैं, परंतु सत्य यही है कि उनकी उपस्थिति से और सहमति से ही अंतिम संस्कार कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहां पुलिस उपस्थित थी। एडीजी ने कहा कि पीड़िता की डेड बॉडी खराब हो रही थी, इसलिए घर के लोगों ने सहमति जातई थी कि रात को ही अंतिम संस्कार कर देना उचित होगा। रात में किए गए अंतिम संस्कार पर हाथरस के जिला अधिकारी ने कहा कि रात को करीब 12:45 बजे पीड़िता का शव लाया गया। मेरी पीड़िता के पिता और भाई से बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। करीब एक से सवा घंटे तक शव वाहन उनके घर पर खड़ा रहा और अंतिम संस्कार के दौरान परिजन वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि करीब 3 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली इस तीन सदस्यीय टीम में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस अधिकारी पूनम को सदस्य बनाया गया है। सीएम ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए टीम को घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समयबद्ध ढंग से जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस दुष्कर्म मामले में की योगी से बात

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के हाथरस दुष्कर्म मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी खुद ट्विटर के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इससे कुछ देर पहले भी एक ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हाथरस दुष्कर्म के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल सात दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फेस्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को चंदपा क्षेत्र में चार लोगों ने एक अनुसूचित जाति की लड़की का सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की, जिससे पीड़िता की जीभ चोटिल हो गई। पीड़िता का इलाज बीते रविवार तक अलीगढ़ में चला लेकिन सोमवार (28 सितंबर) को उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया जहां पीड़िता ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। इसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया और शाम को शव हाथरस के लिए रवाना कर दिया गया। यहां लाकर पुलिस ने बुधवार तड़के करीब 2.45 बजे लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद मामला बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल पुलिस के कृत्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

योगी ने अदालत के फैसले का किया स्वागत कहा कांग्रेस ने वोट बैंक लिए लोगों को फंसाया

लखनऊ, संवाददाता। 28 साल बाद अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को फंसाया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने जारी बयान में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्यमेव जयते के अनुरूप सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया।

मनीषा हत्याकांड में नही मिला न्याय तो करेंगे उग्र आंदोलनः आईएनए

लखनऊ, संवाददाता। इंडियन नेशनलिस्ट एलायंस पार्टी (आईएनए पार्टी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने मनीषा हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार को चेताया है कि यदि मनीषा को न्याय नही मिला तो आईएनए पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने मनीषा के साथ हुई दरिंदगी की खबर सुनी वे तभी से दुःखी एवं विचलित है। विनोद प्रजापति ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि सूबे मे अपराध रोकने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल हो गयी है। बढ़ते रेप के मामलों से यूपी की कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है। बढ़ते अपराध को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित नही है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि देश की बेटी मनीषा को न्याय मिलेगा भी या नही? सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करें। विनोद प्रजापति ने कहा कि उनकी पार्टी हर गरीब, वंचित शोषित व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों वाली एक मात्र पार्टी आईएनए पार्टी है जो सर्व समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द कोई बड़ा एक्शन नही लिया तो आईएनए पार्टी की विंग सुभाष सेवा दल पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।

काकोरी मे जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष एक की मौत कई घायल

लखनऊ, संवाददाता। काकोरी के भटऊ जमालपुर मे आज ग्राम समाज की जमीन को लेकर हुए दो पक्षो के विवाद के बाद विवाद ने खूनी रंग ले लिया जिसमे एक 55 वर्षीय दूध कारोबारी की मौत हो गई और दोनो पक्षो की तरफसे करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। जमीन को लेकर दो पक्षो के बीच हुए खूनी संघर्ष की सूचना के बाद काकोरी पुलिस मौके पर पहुँची और एक दूसरे पर हमला कर रहे लोगो को खदेड़ दिया। खूनी संघर्ष मे घायल हुए सभी लोगो को पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया जहां गम्भीर रूप से घायल 55 वर्षीय दूध कारोबारी को डॉक्टरो ने मृत घोषित कर दिया बताया जा रहा है कि जिस बुजुर्ग की खूनी सघर्ष में मौत हुई है उस बुजुर्ग का दोनो पक्षो के बीच हुए विवाद से कोई सम्बन्ध नही था बुजुर्ग तो दोनो पक्षो मे हो रहे संघर्ष को रोकने का प्रयास कर रहे थे। एसीपी काकोरी ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने तीन लोगो के खिलाफतहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है नामजद किए गए तीनो लोगो को गिरफ्तार कर लिया गया है। काकोरी के भटऊ जमालपुर मे जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षो मे हुए खूनी संघर्ष के बाद गॉव तनाव को देखते हुए मे फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

क्या दलित बेटी को निर्भया जैसा न्याय मिलेगा

लखनऊ, संवाददाता। कुछ महीने पहले ही अपराधियों को संदेश देने की कोशिश में निर्भया के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, अगर कोई फिर से ऐसा अपराध करता है तो उसे इसी तरह सजा दी जाएगी। लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण आज हाथरस में एक बहुत ही गंभीर घटना फिर से घटी जहाँ एक सरकारी अस्पताल में भर्ती दलित बेटी मनीषा की दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में जारी एक बयान में, सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संयोजक मुहम्मद अफाक ने कड़ी चेतावनी दी। मनीषा के अभियुक्तों के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि निर्भया के दोषियों ने किया और सार्वजनिक रूप से फांसी दी गयी। अन्य कोई विकल्प नहीं है क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा घाव भरता जाएगा और फिर बदले की आवाज हल्की हो जाएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि हाथरस की मनीषा जो एक दलित बेटी है।

बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे: जफरयाब जिलानी

लखनऊ, संवाददाता। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपियों को सीबीआई ने बरी कर दिया है। बाबरी केस के पक्षकार रहे जफरयाब जिलानी ने मामले को हाई कोट में चुनौती देगी। मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसम मामले में बैठक कर जल्द ही फैसला लेगा। उन्होंने बात करते हुए कहा कि यह सभी लोग जानते हैं कि छह दिसम्बर 1992 को किस तरीके से अयोध्या में सरेआम बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कानून की धज्जियां उड़ायी गयीं। उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय ने भी रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद में पिछले साल नौ नवम्बर को सुनाये गये फैसले में कहा था कि मुसलमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक गैरकानूनी कृत्य था। जफरयाब जिलानी ने कहा कोई मुजरिम है या नहीं, यह तो अदालतों को ही तय करना होता है। अब मुस्लिम संगठन मिल हाई कोर्ट में अपील करेगा। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफकोई पुख्ता सबूत नहीं थे।

थाना तालकटोरा की पुलिस ही उड़ा रही है महिला सुरक्षा की धज्जियां

लखनऊ, संवाददाता। थाना तालकटोरा की पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय खुद उनका उत्पीड़न कर रही है। पीड़िता की शिकायत सुनने के बजाय और आरोपी को सबक सिखाने के बजाय खुद महिला को ही फर्जी मुकदमें में फसाने की धमकी देकर चुप रहने को कहा जा रहा है। मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र के पथरकटा का है। जहां रहने वाली विधवा गुरप्रीत ने अपनी दो बच्चियों के साथ हुयी मारपीट व छेड़खानी की सूचना 112 पर दी थी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर आकर मामला शान्त करा दिया था। गुरप्रीत ने बताया कि रात को पुनः आरोपी संदीप सैनी ने शराब के नशे में गाली-गलौज की। पीड़िता ने बताया कि थाने पर तैनात उप-निरीक्षक सरफराज खान ने घर आकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उससे बीस हजार रूपयों की मांग की और धमकाया कि रूपये न देने पर विभिन्न संगीन धाराओं में केस दर्ज करा देगें।

मुख्यमंत्री ने 06 एल-2 कोविड चिकित्सालयों का लोकार्पण किया

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' का पालन करना अत्यन्त आवश्यकः सीएम योगी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल माध्यम से जनपद मीरजापुर, भदोही, शामली, बरेली, अमेठी तथा सन्त कबीर नगर के 06 एल-2 कोविड चिकित्सालयों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट भी आज सम्पन्न हुए हैं, यह एक रिकॉर्ड है। प्रत्येक जनपद में एल-01 चिकित्सालय की श्रृंखला, एल-2 डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय की स्थापना और उच्च चिकित्सा संस्थान व मेडिकल कॉलेजों में एल-3 कोविड चिकित्सालय के निर्माण को तेजी से बढ़ाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही, रिकवरी रेट को बेहतर करके आम जनमानस में विश्वास पैदा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब प्रदेश में टीम वर्क से सम्भव हुआ। इस टीम वर्क का ही परिणाम है कि आज हम 06 एल-2 कोविड चिकित्सालय प्रदेशवासियों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में 36 ऐसे जिले थे, जहां वेंटिलेटर या एच0एफ0एन0सी0 की कोई सुविधा नहीं थी। आज सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और एच0एफ0एन0सी0 की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सामने चुनौतियां थीं। प्रदेश की 24 करोड़ आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ ही टेस्टिंग क्षमता को विकसित करने की। जिस प्रदेश में टेस्टिंग की कोई क्षमता न रही हो, उस प्रदेश द्वारा आज डेढ़ लाख टेस्ट प्रतिदिन किये जाने की क्षमता का विकास यह दर्शाता है कि कोविड-19 हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार पूरी गम्भीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े जनपदों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से अपील की कि हमें हर हाल में संक्रमण को रोकना व सतर्क रहकर चेन को तोड़ना होगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के उपचार का सबसे अच्छा तरीका बचाव है।

सभी मन्दिरों से विवादित ढांचे हटने तक शान्त नहीं बैठेगी हिन्दू महासभा

राम मन्दिर के विवादित ढांचे विध्वंस मामले में निर्णय का किया स्वागत

लखनऊ, संवाददाता। अखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश ने आज यहां राम मन्दिर के विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में आरोपियों की बरी किये जाने के सीबीआई के विशेष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुये कहा है कि देश में हिन्दूओं के आस्था के प्रतीक सिर्फ भगवान राम मन्दिर ही तक सीमित नहीं है बल्कि मथुरा काशी सहित देश के हजारों मन्दिरों को मुगलकाल के दौरान तोड़कर बनाये गये विवादित ढांचे नहीं हटते है तब तक हिन्दू समाज शान्त नहीं बैठने वाला है। हिन्दू महासभा के प्रदेश प्रभारी ऋषि त्रिवेदी और प्रवक्ता पंकज कुमार तिवारी ने कहा कि राम मन्दिर के विवादित ढांचे के विध्वंस मामले के निर्णय आने के बाद देश में हिन्दू महासभा मथुरा काशी, लक्ष्मण टीला, भोजशाला सहित देश के हजारों मन्दिरों के वास्तविक स्वरूप में लौटाने के लिये संघर्षरत रहेगी। हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा कि हालांकि राम मन्दिर निर्माण उच्चतम न्यायालय के निर्णय सराहनीय रहा है, लेकिन उसके बदले पांच एकड़ जमीन दिये जाने पर पार्टी आज भी सहमत नहीं है। हालांकि हिन्दू समाज के उदारवादी होने का ही परिणाम है कि उसने हमेशा झुककर समझौता किया है। हिन्दू महासभा के नेताओं ने कहा कि पार्टी अन्य धार्मिक स्थलों जो मुगलकाल के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये थे, उन्हें विवादित ढांचे से मुक्त कराने के लिये कारसेवकों की टीम तैयार करने की रणनीति पर विचार कर रही है और जल्द ही अन्तिम रूप देकर सड़कों पर उतरेगी। इसके लिये पार्टी तेजी के साथ जहां सदस्यों को जोड़ रही है वहीं सभी इकाईयों को सक्रिय करने के लिये तत्परता के साथ काम कर रही है। जिसके परिणाम सामने आने शुरू हो गये है, और जल्द ही पार्टी एक नई शक्ति के रूप में सड़कों पर दिखायी देगी। आज यहां सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय पर हिन्दू नेताओं ऋषि त्रिवेदी और पंकज तिवारी ने बताया कि विध्वंस ढांचे के मामले में सभी आरोपियों को बरी होना तय था क्योंकि लुटेरे बाबर द्वारा बनाया गया विवादित ढांचा भगवान राम मन्दिर के लिये नासूर बना हुआ था, जो बीते छह दिसम्बर 1992 को हुयी कारसेवा के दौरान साजिश के तहत नहीं बल्कि कारसेवा के लिये उमड़े रामभक्तों के अपार जनसमूह की आस्था के आगे ढह गया था।

हाथरस में हुई प्रशासनिक लापरवाही के दोषी हो दण्डितः आइपीएफ

लखनऊ, संवाददाता। हाथरस में गैंगरेप की पीड़िता दलित युवती की दिल्ली की सफदरगंज अस्पताल में पंद्रह दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद हुई मृत्यु की दर्दनाक घटना पर आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एस. आर. दारापुरी ने संवैधानिक प्रमुख व महिला होने के नाते राज्यपाल को पत्र भेजकर प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला हिंसा की घटनाओं में तत्काल हस्तक्षेप कर प्रदेश सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में हाथरस की अमानवीय व बर्बर घटना में लापरवाही बरतने और समय से एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही न करने और उसे समुचित इलाज न दिलाने वाले दोषी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दण्डित करने, महिलाओं पर हो रही हिंसा की घटनाओं के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जवाबदेह बनाने और महिलाओं के साथ हिंसा, बलात्कार, हत्या की घटनाओं में तत्काल राहत पहुंचाने वाली 181 वूमेन हेल्पलाइन और महिला समाख्या जैसी महिलाओं के लिए हितकारी योजनाओं को पूरी क्षमता से चलाने की मांग की। पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव गृह और महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस को भी भेजी गयी है। पत्र में दारापुरी ने कहा कि हाथरस में दलित युवती के साथ 14 सितम्बर 2020 को गैंगरेप की घटना हुई थी और भारी जनदबाव के बाद 19 सितम्बर 2020 को उसकी एफआईआर पंजीकृत हो पायी। उसे काफी लम्बे समय तक अलीगढ़ के अस्पताल में इलाज हेतु रखा गया और वहां समुचित इलाज न मिलने पर ही उसे दिल्ली एम्स भेजा गया।

हाथरस की घटना को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां

लखनऊ, संवाददाता। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में काफी गुस्सा है। इसी क्रम में राजनीतिक पार्टी भी योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर आज लखनऊ में प्रदर्शन किया साथ ही सीएम का पुतला भी फूंका सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काफी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाने का प्रयास भी किया लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इस पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जम कर लाठी चार्ज किया। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश में कानून का अपराधियों में डर नहीं है। सरकार अपराधियों को बचा रही है। लोकतंत्र में जनता की अवाज को योगी सरकार दबा रही है। बता दें कि हाथरस में दलित युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत की गई। जिसे लेकर लोगों का आक्रोश झलक रहा है।

गैंगरेप पीड़िता के संस्कार पर बोलीं मायावती, कहा-सरकार और पुलिस के रवैए से नहीं लगता न्याय मिलेगा

लखनऊ, संवाददाता। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आधी रात को जिस तरीके से पीड़िता का अन्तिम संस्कार किया गया वह लोगों में काफी संदेह व आक्रोश पैदा करता है। बीएसपी पुलिस के ऐसे गलत रवैये की

कड़े शब्दों में निन्दा करती है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, 'यूपी पुलिस द्वारा हाथरस की गैंगरेप दलित पीड़िता के शव को उसके परिवार को न सौंपकर उनकी मर्जी के बिना व उनकी गैर-मौजूदगी में ही कल आधी रात को अन्तिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह व आक्रोश पैदा करता है। बीएसपी पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़े शब्दों में निन्दा करती है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो यह बेहतर होगा, वरना इस जघन्य मामले में यूपी सरकार व पुलिस के रवैये से ऐसा कतई नहीं लगता है कि गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय व दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी।

हाथरस रेप पीड़िता के अंतिम संस्कार में प्रशासन ने कानून परम्पराओं और हिन्दू रीति रिवाज के साथ बलात्कार किया

लखनऊ, संवाददाता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा आउट रीच कमेटी, उत्तर प्रदश के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत को शर्मसार करने वाली बलात्कार की घटना से पूरा दश ही नहीं बल्कि दुनिया में इंसानियत शर्मसार हुई है। एक 19 वर्ष की बेटी को जिस तरह 4 बलात्कारियों ने जबरन दिन दहाड़े खेत में खींचकर उसके साथ बलात्कार किया, और प्राणघातक चोटे पहुँचाई, वह उसकी मृत्यु का कारण बनी। बाद में पीड़िता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिली, जैसा कि उसके मॉ- बाप ने आरोप लगाया है, यह उत्तर प्रदश सरकार के अमानवीय चेहरे को उजागर करता है। यही नहीं दिल्ली भी उसे तब ले जाया गया जब उसकी सॉसे उखड़ रही थी और चन्द सॉसे ही बची थी। काश! यदि उसे पहले समय रहते दिल्ली भेज दिया गया होता तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती। उसके बाद जो कुछ हुआ वह उत्तर प्रदश शासन एवं प्रशासन के क्रूर चेहरे को उजागर करता है, पीड़िता के बाप-भाई को अस्पताल से बाहर कर दिया गया, और प्रशासन उनसे झूँठ बोलता रहा कि आपकी बेटी अंदर है, और प्रशासन उसके पार्थिव शरीर को बिना उसके बाप- भाई को बताये हाथरस लेकर चले गये, उसकी मॉ और परिवार जन बेटी के अंतिम दर्शन की भीख मांगते रहे, और बेटी को घर की देहली पर, जहॉ वह पैदा हुई, वहॉ ले जाने के लिये गिड़गिड़ाते रहे किन्तु तानाशाहों ने जबरन उस बेटी को एक खेत में ले जाकर रात्रि 2:30 बजे लकड़ी पर पेट्रोल डालकर जला दिया, ऐसा आरोप उसके परिजन लगा रहे हैं। श्री तिवारी ने कहा है कि क्या उस बेटी का दाश यही था कि वह एक गरीब मॉ- बाप की बेटी थी ? और दलित थी। क्या उसके मॉ- बाप अमीर होते, और शक्तिशाली होते तो क्या सरकार उस बेटी के साथ ऐसा करती ? श्री तिवारी ने कहा है कि सभी धर्मो में एवं कानून में पार्थिव शरीर को सम्मान देने का विधि विधान है, किन्तु उसकी भी बलि चढ़ा दी गयी। हिन्दू रीति में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता, और पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार उसके परिवार जनों का होता है किन्तु हिन्दू धर्म की सभी मान्यताओं को तोड़कर अपमानित किया गया। जिस बर्बरता का प्रर्दशन शासन एवं प्रशासन अंतिम संस्कार के समय कर रहा था वैसा तो दुर्दान्त अपराधियों के साथ भी नहीं होता, फिर भी यह तो बलात्कार की पीड़िता थी। श्री तिवारी ने कहा है कि उस पीड़िता बेटी के साथ एक बार तो 4 बलात्कारियों ने बलात्कार किया था और आज उसके अंतिम संस्कार में शासन व प्रशासन ने कानून, परम्पराओं और हिन्दू रीति रिवाज के साथ बलात्कार किया, जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे यही कह रहे हैं कि उस पीड़िता बेटी के साथ कोई न्याय करे या न करे किन्तु प्रकृति उसके साथ न्याय अवश्य करेगी, तथा जिन्होंने हिन्दू धर्म, परम्पराओं और रीति रिवाज को अपमानित किया है।

सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर निर्णय लेंगे मुस्लिम संगठनःमौलाना रशीद

लखनऊ, संवाददाता। देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत के बुधवार के फैसले पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि अब मुस्लिम संगठन मिल-बैठकर तय करेंगे कि इसके खिलाफ आगे अपील करनी है या नहीं। रशीद ने बातचीत में कहा, विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। यह सभी लोग जानते हैं कि छह दिसम्बर 1992 को किस तरीके से अयोध्या में सरेआम बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कानून की धज्जियां उड़ायी गयीं। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय ने भी रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद में पिछले साल नौ नवम्बर को सुनाये गये फैसले में कहा था कि मुसलमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक गैरकानूनी कृत्य था। रशीद ने कहा, कोई मुजरिम है या नहीं, यह तो अदालतों को ही तय करना होता है। अब मुस्लिम संगठन मिल-बैठकर तय करेंगे कि आगे अपील करनी है या नहीं। अपील करने का कोई फायदा होगा भी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।श्श् उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फैसलों का सम्मान करते आये हैं और हमेशा करते रहेंगे। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफकोई पुख्ता सबूत नहीं थे।

वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण

संयुक्त परिषद ने जताया विरोध, मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन

लखनऊ, संवाददाता। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्गत किए गए उस आदेश पर, जिसमें वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम करने का आदेश जारी किया गया है पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अवगत कराया है कि वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन घटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन ने 29 सितंबर 2020 को एक साथ आदेश जारी कर एसीपी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से चली आ रही परंपरा को समाप्त करते हुए वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ के कर्मचारी से कम कर दिया है। शासनादेश के हवाले से कहा गया है कि एसीपी व्यवस्था से संबंधित 2014 के शासनादेश में जहां कहीं भी कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन मिल रहा था, वहां कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन देने का आदेश था । परंतु अब शासन ने इस आदेश में संशोधन करते हुए वरिष्ठ कर्मचारी को कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है। शासन द्वारा जारी आदेश कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्यवाही है, इस आदेश से वरिष्ठ कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा एवं वह अपने मातहत से काम लेने में दुविधा महसूस करेगा। एसीपी व्यवस्था कर्मचारियों को प्रमोशन ना होने की स्थिति लाभ देने के लिए बनाई गई है। प्रदेश के विभागों में प्रमोशन की स्थिति यह है कि 15 - 20 वर्षों तक प्रमोशन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को एसीपी के माध्यम से वित्तीय लाभ मिल रहा था। 2014 के शासनादेश के अनुसार किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त ग्रेड वेतन अथवा एसीपी की व्यवस्था में अगला प्राप्त ग्रेड वेतन किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे एसीपी में ग्रेड वेतन से कम होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वेतन दिए जाने का प्रावधान था लेकिन अब यह प्रावधान बदल दिया गया है। इस आदेश से सरकारी विभागों में प्रशासनिक दिक्कतें भी उत्पन्न हो जाएगी। यदि कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन पाएगा तो वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ कर्मचारी पर प्रशासनिक नियंत्रण कैसे कर सकता है? संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया है।

निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी कार्यालयों में सन्नाटा, मोहद्दीपुर में प्रदर्शन

गोरखपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बुधवार को दूसरे दिन भी दोपहर 12 बजे तक सभी कर्मचारी और अधिकारी कार्यालयों से अपने घर चले गए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों का आंदोलन उपभोक्ताओं पर भारी पडने लगा है। अफसर व कर्मचारी कार्यालयों से दोपहर 12 बजे तक निकल गए। इसके चलते यहां अपनी समस्या लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं को वापस लौटना पड़ा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों की तरफ से दोपहर बाद 2 बजे के बाद से मोहद्दीपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने

धरना दिया गया। यहां वीके चौधरी ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में कर्मियों ने अपने काम का लोहा मनवाया है।, लेकिन निगम व सरकार निजीकरण पर आमादा हैं। वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण के कारण कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं की यह परेशानी सरकार के कारण हो रही है। सरकार नहीं चाहती कि उपभोक्ता सकून से रहें। मजबूर होकर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण के बाद बिजली की हालत काफी खराब हो जाएगी। न तो समय से बिजली बिल जमा हो पाएगा और न ही सही से बिजली मिल सकेगी। प्रदेश भर के बिजली अधिकारी और कर्मचारी एकजुट हैं। सरकार या तो आंदोलनकारियों की बात मानेगी अन्यथा बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करेगी। उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। धरने में अशोक कुशवाहा, रुद्र प्रताप सिंह, सरोजिनी सिंह, नरसिंह मौर्य शिवम चौधरी, बृजेश त्रिपाठी, राहुल श्रीवास्तव, विपिन सिंह, मनीष राय, संदीप श्रीवास्तव, राम अवतार यादव, विनीता सिंह, पूजा सिंह, नीति मिश्रा, रंजना कनौजिया, रमेश सहानी, शशि कपूर, हरिश्चंद्र आदि मौजूद रहे।

विद्युत मजदूर संगठन ने शुरू किया सत्याग्रह

आंदोलन को समर्थन देने के लिए विद्युत मजदूर संगठन ने मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने सत्याग्रह शुरू किया। इस दौरान अजय कुमार शाही, मनीष राय, विनोद कुमार श्रीवास्तव, शंभूशरण श्रीवास्तव, जगरनाथ यादव, अभिलेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह, रामबचन आदि मौजूद रहे।

छोड़ा बिजली निगम का ग्रुप

बिजली निगम के इंजीनियरों ने निगम से जुड़े सभी वाट्सएप ग्रुपों को छोड़ दिया। उनका कहना था कि निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने तक वह न तो किसी वीडियो कांफेंड्क्षसग में हिस्सा लेंगे और न ही किसी बैठक में जाएंगे।

इको गार्डन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत गिरफ्तार सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने कैंडिल जलाकर हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की।

निजीकरण और एनपीएस के विरोध में 2 अक्टूबर को अटेवा मनाएगा संकल्प दिवस

गोरखपुर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संघर्षरत संगठन अटेवा (ऑल टीचर्स एंड एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन) के आह्वान पर जिले के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी गांधी जयंती के दिन एनपीएस तथा निजीकरण के विरोध में संकल्प दिवस मनाएंगे । अटेवा तथा एनएमओपीएस इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर जिले के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपने-अपने विद्यालयों कार्यालयों ब्लॉक तहसील और गांव में गांधी प्रतिमा या फोटो के समक्ष पुष्प माला अर्पित करेंगे। पुरानी पेंशन के लाभ तथा निजी करण के नुकसान पर चर्चा करेंगे। राम धुन गाएंगे तथा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सत्तासीनों को सम्मति आए और वह पुरानी पेंशन बहाल करें तथा निजी करण के फैसले को वापस लें।

संकल्प दिवस के दिन सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी इस बात का संकल्प लेंगे कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल ना हो जाए, दमनकारी एनपीएस तथा निजी करण की नीतियां पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए तब तक निरंतर अटेवा का संघर्ष जारी रहेगा । जिला सोशल मीडिया प्रभारी गोरखपुर रामसनेही प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर संकल्प दिवस के दिन निजीकरण भारत छोड़ो हेस्टैग के साथ संकल्प दिवस की तस्वीरों को लगाते हुए ट्विटर पर अभियान चलाएंगे तथा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन बहाल करने तथा निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग करेंगे । अटेवा गोरखपुर के जिला संयोजक प्रताप नारायण सिंह ने अटेवा के सभी जिला तथा ब्लॉक पदाधिकारियों, जिले के सभी शिक्षकों , कर्मचारियों , अधिकारियों से गांधी जयंती के दिन संकल्प दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय सलिल विश्नोई जी को श्रीमद भगवतगीता पुस्तक भेंट कर स्वागत किया

रुद्र प्रताप सिंह। लखनऊ मलिहाबाद विधान सभा की भाजपा की बैठक का भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई का पवित्र पुस्तक श्रीमद्भागवत गीता भेट कर अखिलेश अवस्थी ने स्वागत किया और मलिहाबाद ब्लॉक सभागार में हुई बैठक जिसमे पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाने है इस विषय पर चर्चा हुई जिसमे मुख्य अतिथि श्रीमान सलिल विश्नोई जी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी

रहे कार्यक्रम में विधायक जय देवी कौशल विजय मौर्या जिला महामंत्री जी मूलचंद जी विधानसभा संयोजक अखिलेश अवस्थी युवा मोर्चा जिला मंत्री मीनू वर्मा तथा सभी मंडल अध्यक्ष मंडल समित सक्टर संयोजक प्रभारी बूथ अध्यक्ष बूथ प्रभारी सेक्टर संयोजक सूरज चौरसिया समाजसेवी विनय प्रताप सिंह उपस्थित रहे बूथ को मजबूत करने पर मुख्य अतिथि जी ने पार्टी को मजबूत करने का तौर तरीका बताया और सभी पदाधिकारी एक एक बूथ की जिम्मेदारी ले साथ ही प्रवास संबाद कार्यकर्ताओ के साथ महीने में एक बार बूथ की बैठक अवश्य करे ताकि पार्टी को आगे मजबूती मिल सके।

सामुदायिक शौचालय बनने पर ग्रामीणों में खुशी-प्रधान की हो रही प्रशंसा

नौतनवा! ब्लाक के ग्रामसभा निपनिया आगनबाड़ी केंद्र के पास सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी से ग्रामीण बहुत खुश थे। ग्रामीणों ने स्वच्छता की ओर उठाए गए सरकार के कदम को सराहा। सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को खुले में शौच जाने से छुटकारा मिलेगा। वैसे भी सरकार स्वच्छ मिशन के अंतर्गत हर घर शौचालय की मुहिम चलाई थी। इस योजना के तहत कई परिवार लाभांवित भी हुए। किसी कारणवश या छूट गए लोगों के लिए यह सार्वजनिक शौचालय मील का पत्थर साबित होगा। ग्रामसभा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पहली बार कराया गया है। अब इस योजना का लाभ पुरे ग्रामसभा के लोगों को मिलेगा। आने-जाने वाले राहगीर भी सुलभ शौचालय का उपयोग कर सकेंगे। प्रधानपति

अकबर अली ने बताया कि सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत के लोगो द्वारा किया गया है। इसकी कुल अनुमानित लागत पांच लाख रुपये है। सुलभ शौचालय में महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय और स्नानागार है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण हर ग्रामसभा में किया जाना आवश्यक है। स्वच्छ मिशन के तहत सरकार हर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करा रही है, जो सराहनीय है। रामचंद्र,राजू त्रिपाठी,भरत,रामनयन, रामबेलाश,व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

बाइक सवार बदमाशों ने प्रधान के घर पर चलाई गोलियां,दहशत का माहौल

गोरखपुर/ सहजनवा थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव में मंगलवार की देर रात नकाब पोश बाइक सवार बदमाशों ने प्रधान के घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचते बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस का खोखा बरामद किया। प्रधान की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर भूमि विवाद में गोली चलाने का आरोप लगाया है। टिकरिया गांव में प्रधान अखिलेश सिंह खलीलाबाद क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में वर्ष 2016 से जेल में बंद हैं। मंगलवार की रात तकरीबन 11 बजे बाइक सवार तीन-चार नकाबपोश बदमाश उनके घर पहुंचे। पहले वह चाहरदीवारी का गेट खोलने की कोशिश किए लेकिन गेट नहीं खोलने पर उनके घर पर ईंट-पत्थर और गोली चलाने लगे। ताबड़तोड़ गोली चलने की आवाज सुनकर गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचते तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना की सूचना पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीन कारतूस का खोखा बरामद की। मौके पर ईंट-पत्थर भी बिखरे पड़े हुए थे।

प्रधान की पत्नी रंजना सिंह ने बुधवार की सुबह थाने पर तहरीर देकर बताया कि उनके पति का एक बेशकीमती भूमि को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। उस मामले में पीछे हटने का दबाव बनाने के लिए उनके घर पर फायरिंग कराई गई है। उन्होंने तीन लोगों के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी है। सहजनवा थानेदार देवेन्द्र लाल ने बताया कि घटना की तहरीर मिल गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। प्रापर्टी डीलिंग का काम करता है प्रधान टिकरिया गांव के प्रधान अखिलेश सिंह प्रापर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। वह संतकबीरनगर जिले में प्रापर्टी के काम से जुड़े हुए है। वर्ष 2015 में खलीलाबाद के बरदहिया बाजार में हुई एक हत्या के मामले में वह आरोपित हैं। 10 अक्टूबर 2016 से ही वह जेल में बंद हैं।

सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक बालिका को दिया श्रद्धांजलि

गोरखपुर/समाजवादी पार्टी के जिला जिला सचिव कपिल मुनि यादव के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौराहे से कैंडल मार्च निकाला।

जो टाउन हॉल के गांधी प्रतिमा पर जाकर संपन्न हुआ। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने राज्य की योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से बालिका के साथ दुष्कर्म उसके बाद दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पूरे प्रदेश में जंगलराज का माहौल है और तो और पुलिस ने मृतक बालिका के शव को उसके परिजनों को ना सौंपते हुए जबरन दाह संस्कार कर दिया।

जिसकी हम पूरी तरीके से घोर निंदा करते हैं।और दोषियों के लिए फांसी की मांग करते है।

शादी का झांसा देकर दो साल से दुष्कर्म करने का आरोप

बस्ती। जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी का झांसा देकर दलित परिवार की बेटी संग दो साल से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही अभिषेक नामके युवक पर लगा है। दलित पीड़िता ने मीडिया दस्तक को बताया कि युवक उससे करीब 4 सालों से अश्लील बातें मोबाइल पर करता था। कई बार उसने समझाने का प्रयास किया। बाद में शादी का वादा कर उसका यौन शोषण करता रहा। मां बाप की गैरमौजूदगी में वह एक बार घर में आया और उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद मुंह बंद रखने की धमकी देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। शादी की बात करने पर वह वादे से मुकर गया और कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप यह भी है कि युवक ने पीड़िता और मां के कुछ जेवर भी ले लिये और शादी के चक्कर में सबको उलझाये रखा। लोकलाज के कारण वह अपने मां बाप से यह बात छिपाती रही लेकिन खुद को युवक की ट्यूह रचना में उलझता देख उसने माता पिता से सारी बात बताया। पिता ने वाल्टरगंज पुलिस और युवक के पिता से शिकायत की। लेकिन दलित परिवार की फरियाद दबकर रह गयी। मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ा। युवती का कहना है कि उसे शादी का वादा किया, अपना वादा निभाये। वहीं पिता ने कहा उसकी बेटी को उसने कहीं का न छोड़ा। अब हम उसे लेकर कहां जाये, समझ में नही आ रहा है। फिलहाल पिता पुत्री ने आरोपी से जान का खतरा बताते हुये वाल्टरगंज पुलिस से न्याय की फरियाद की है।

पोखरे में डूबने से नाबालिग लड़की की मौत

महराजगंज! परसा मलिक। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा महरी टोला घोड़ाहवा निवासी 17 वर्षीय सुमन पुत्री रामबेलास यादव का बुधवार की सुबह पोखरे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतिका सुमन बुधवार की सुबह शौच के लिए गांव से बाहर पश्चिम दिशा में स्थित पोखरे के तरफ गई थी, जहां पोखरे में पैर फिसलने से डूबकर उसकी मौत हो गई।

बताया जाता है कि शौच के लिए गई युवती जब काफी देर बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने छानबीन करना शुरू कर दिए। जहां खोजबीन करते हुए पश्चिम स्थित पोखरे के तरफ गए जहां पोखरे में सुमन का शव दिखाई दिया परिजन सहित ग्रामीणों ने मौके की जानकारी परसामलिक पुलिस को दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोखरे से शव को बाहर निकलवाया तथा कागजी कार्यवाही के बाद शव को थाने लाई। जहां से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संदर्भ में एसआई अनील कुमार राय ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार सुमन सुबह शौच के लिए पोखरे के तरफ गई थी जहां पैर फिसलने से पोखरे में डूब कर उसकी मौत हो गई। जहां शव को कागजी कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

हाथरस की दलित बेटी के इंसाफ के लिए प्रदेश कांग्रेस सड़क पर उतरी, पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लखनऊ सहित कई जिले में कांग्रेसी हुए घायल

■ योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। आपके शासन में न्याय नहीं, सिर्फ अन्याय का बोलबाला है: प्रियंका गांधी ■ कितने संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं आप योगी जी- प्रियंका गांधी ■ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव करने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार, लाठीचार्ज में कई नेता एवं कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल ■ वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का कांग्रेसियों ने किया घेराव ■ दलित बालिका के साथ दरिन्दगी पर योगी सहित महिला राज्यपाल की खामोशी क्यों, चुप्पी का राज क्या है: अजय कुमार लल्लू ■ देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चुप क्यों हैं?- अजय कुमार लल्लू ■ प्रदेश में बढ़ती गैंगरेप और हत्या जैसी जघन्य घटनाओं के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री गद्दी छोड़े, पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है- अजय कुमार लल्लू

लखनऊ। उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी ने हाथरस की दलित बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या तथा परिजनों की गैर मौजूदगी में पुलिस द्वारा शव को आधी रात जलाये जाने पर दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत आज राजधानी में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू सहित सैंकड़ों कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस के सामने अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया, जहां से प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इको गार्डेन भेज दिया गया। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि - रात को 2.30बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे लेकिन हाथरस की पीड़िता के शव को उ0प्र0 प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीना और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर दुगुना अत्याचार किया। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। आपके शासन में न्याय नहीं, सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। इसके पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ट्विट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है। उन्होने कहा है कि - ''मैं यूपी के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं -परिजनों से जबर्दस्ती छीनकर पीड़िता के शव को जलवा देने का आदेश किसने दिया? पिछले 14 दिन से कहां सोए हुए थे आप? क्यों हरकत में नहीं आए? और कब तक चलेगा ये सब? कैसे मुख्यमंत्री हैं आप''।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि एक दलित की बेटी न्याय की आस लिए मर गई। महामहिम चुप क्यों हैं उनकी चुप्पी का राज क्या है, महिला होने के नाते अभी तक उनका एक भी बयान क्यों नहीं आया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सहित प्रदेश के मुखिया की चुप्पी का राज क्या है? कौन जवाब देगा देश को, देश रो रहा है, बिलख रहा है। देश की बेटी सुरक्षित नहीं हैं, क्या इसी तरह की घटनाएं निरन्तर उ0प्र0 में होती रहेंगी और सरकार संवेदनहीन बनी रहेगी। आज हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने जा रहे थे मुख्यमंत्री के गुर्गों द्वारा लाठी-डण्डों से हमें पीटा गया और गिरफ्तार किया गया। क्या न्याय मांगने वालों पर लाठी चलाई जाएगी। क्या पीड़ित बहन के लिए संघर्ष की बात करने पर लाठी चलाकर दमन किया जाएगा। उन्होनें कहा कि योगी सरकार ने इन्सानियत को शर्मसार किया है। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ें, आपको इस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। प्रदेशव्यापी आन्दोलन के तहत आज हाथरस में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करके गिरफ्तार किया गया। वहीं हाथरस जाते हुए बदायूं हाईवे पर कांग्रेस महासचिव ब्रम्हस्वरूप सागर, असलम चैधरी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जनपद जालौन, सोनभद्र, चित्रकूट, आजमगढ़, भदोही, चन्दौली समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, कांग्रेसजनों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज कर गिरफ्तार किया। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर जुलूस निकालकर संसदीय कार्यालय का घेराव किया जिस पर भारी पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर गिरफ्तार किया। राजधानी में आज सीएम आवास का घेराव करने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी सहित कांग्रेसजनों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज में श्री अजय श्रीवास्तव अज्जू, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनस रहमान, पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन श्री मनोज यादव, संगठन मंत्री श्री अनिल यादव, मीडिया संयोजक श्री ललन कुमार को गंभीर चोटें आयीं। गिरफ्तार होने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ला, प्रदेश सचिव श्री रमेश शुक्ला, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम, श्री तरूण पटेल, जिलाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, शहर अध्यक्ष श्री मुकेश सिंह चैहान, श्री शिव पाण्डेय, श्री दिलप्रीत सिंह 'डीपी', श्री शिवम त्रिपाठी, श्री ज्ञानेश शुक्ला, मो0 तारिक सिद्दीकी, मुशर्रफ इमाम, विकास सक्सेना, हाशिम अली, रंजीत भारती आदि भारी संख्या में कांग्रेसजन शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर सायं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कनिष्क पाण्डेय के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज कर गिरफ्तार कर लिया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के कपड़े फट गये व हाथ-पैर टूट गये। गिरफ्तार होने वालों में श्री कनिष्ठ पाण्डेय के अलावा श्री शिवम त्रिपाठी, श्री ज्ञानेश शुक्ला, श्री नितिन शुक्ला, श्री अवनीश शुक्ला, श्री राहुल अवस्थी, श्री रोहित अवस्थी, मो0 तलहा , अजीत सिंह , संदीप पाल धनगर , सैय्यद इमरान आशीष मिश्र सुधांशु बाजपेयी लल्लू कन्नौजिया हसन मेहंदी , आदित्य सिंह सहित कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे।

लोकतंत्र के लिए कानून का शासन जरूरी

पांच सितारा वैचारिक अनुष्ठान दिल्ली की लुटियन संस्कृति का हिस्सा है. इनमें मंत्रियों, हॉलीवुड-बॉलीवुड सितारों और उद्योगपतियों की चकाचौंध रहती है. अक्सर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं. मगर, असली समां बनता है मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों से, क्योंकि वीआइपी दर्शक इन्हीं को सुनने आते हैं और संयोजकों का रसूख बढ़ाते हैं. मेरी दिलचस्पी रहती है वक्ताओं से अधिक विशिष्ट दर्शकों की प्रतिक्रियाओं में. सभाओं के कुछ अलिखित नियम होते हैं, जैसे कि सवाल दोस्ताना हों और अदब से परोसे जायें, अतिथि देवो भव! ऐसे ही एक सम्मेलन में एक न्यूज एंकर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ शहद भरे संवादों के बाद, एक गंभीर सवाल पूछ डाला- झूठे मुकाबलों में कथित अपराधियों को 'ठोके' जाने (यानी उनकी हत्या) पर. योगी जी का छोटा सा उत्तर था 'तो क्या आरती उतारूं?' परिष्कृत दर्शकों ने ठहाका लगाते हुए जोरदार तालियां बजायीं. जैसे विधि और विधान किताबी बातें हों. बस उठाओ और 'ठोक' दो- इंसानों के साथ-साथ न्याय प्रणाली को भी. मुझे दर्शकों का वो ठहाका आज भी परेशान करता है. क्या प्रबुद्ध भारत का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ चुका है? इसकी पृष्ठभूमि यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस संदिग्ध मुठभेड़ों में पिछले कुछ वर्षों में 4,000 से ज्यादा इंसानों को मार चुकी है. हर दिन, हर कुछ घंटों में, एक सी घटनाएं होती हैं और कुछ लाशें बरामद हो जाती हैं. कहानियां विचित्र मगर समरूपी हैं- या तो वह पुलिस के कहने पर नहीं रुका और गोलियां चलाने लगा या राइफल छीनकर पुलिसकर्मियों पर झपटा और पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के दौरान ढेर हो गया. मामले अदालतों में हैं, मगर अधिकतर में लीपापोती हो चुकी है. कई याचिकाएं खारिज भी हो चुकी हैं. योगी जी की छवि परिश्रमी और ईमानदार नेता की है, मगर क्या किसी सभ्य समाज में हत्या को स्टेट पॉलिसी बनाया जा सकता है? वैसे ही जैसे कुछ देशों ने आतंकवाद को बनाया है? क्या कोई विवेकशील व्यक्ति कहेगा कि देश आतंकी है, मगर नेता बड़ा ईमानदार है? क्या भागलपुर में 40 साल पहले 31 कथित अभियुक्तों की आंखें फोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को, या कथित चोरों के हाथ काटने वाले देशों को, दुनिया में कोई न्यायपरक मानता है? प्रश्न यह भी है कि क्या अंततः अदालत की आंखों पर भी पट्टी बांधी जा सकती है? इसके लिए आवश्यक है कि तफ्तीश इकतरफा हो और लीपापोती की गुंजाइश रखी जाये. मगर एक भी सही अधिकारी अन्याय को रोक सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि सही अधिकारियों को उचित दूरी पर रखा जाये और प्रभावी नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित हों. दिल्ली दंगों की चार्जशीट इस इकतरफा जांच का एक नमूना है. इसीलिए 2006 में प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफइंडिया मामले के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में राज्यों को अपराधों की जांच के लिए अलग विंग बनाने का, और ऐसे आयोग के गठन का निर्देश दिया गया था, जिससे पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों, तबादलों और पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप रोका जा सके. इसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने का, जो हर राज्य और जिले में होनी आवश्यक हैं. इससे नागरिक पुलिस ज्यादतियों पर नजर रख सकें. राज्यों ने अभी तक इसपर पूर्णतः अमल नहीं किया है, जबकि इसे न करने का या देरी करने का विकल्प उनके पास नहीं है, क्योंकि यह आदेश अब देश का कानून है. मगर असलियत यह है कि राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि पुलिस न्याय व्यवस्था के लिए नहीं, सत्ताधारी शासकों के लिए काम करे जैसे अंग्रेजों के जमाने में करती थी. यदि हम पुलिस सुधारों के प्रति गंभीर हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि पुलिस का यह गोरखधंधा दशकों से सभी राज्यों में चल रहा है. इसमें सभी बड़ी पार्टियां शामिल हैं. तमिलनाडु में, जहां एआइएडीएमके की सरकार है, थूतूकुडी में 62 वर्षीय दुकानदार जयराज और उनके 32 वर्षीय पुत्र बेनिक्स को पुलिस ने थाने में पीट-पीटकर मार डाला. उन पर आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखी और पुलिस को पीठ पीछे बुरा भला कहा. जो बात पुलिस ने सुनी ही नहीं, वह उन्हें इतनी चुभी कि उन्होंने बाप-बेटों की जान ले ली, वह भी उस 'अपराध' के लिए जिसके सिद्ध होने पर अधिकतम सजा तीन महीने की कैद थी. दूसरा मामला तेलंगाना का है, जहां एक 26 वर्षीया मासूम महिला की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद पुलिस और तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की खुलकर आलोचना हुई थी और जनता सड़कों पर आ गयी थी. पुलिस ने चार संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर देर रात गोलियों से भून दिया. कहानी वही थी कि राइफल छीनने की कोशिश हुई. पुलिस ही जांचकर्ता, जज और जल्लाद बन गयी और उसे इस हत्या के लिए खूब शाबाशी मिली. दक्षिण के दोनों मामलों में और उत्तर प्रदेश के झूठे मुकाबलों में एक और समानता है- मरनेवाले लगभग सभी 'आरोपी' गरीब थे. जो प्रभावशाली हैं वो अदालतों में जायेंगे जैसे कि बलात्कार और हत्या के कुख्यात आरोपी और 'बापू' कहलाने वाले आसाराम, स्वयं को 'इंसान' कहनेवाले राम रहीम और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर. एनकाउंटर की क्या यही पॉलिसी हैरू गरीब है तो 'ठोक' दोय दबंग है तो अदालत भेजो? संविधान का आर्टिकल-21 जीवन और व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है. आर्टिकल-22 में यह अनिवार्य है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले उसकी वजह बतायी जाये और कानूनी सलाह लेने या पैरवी की अनुमति दी जाये. जिन देशों में ऐसा नहीं है वहां न्याय प्रणाली चरमरा जाती है और उन्हें 'फेल्ड स्टेट' कहा जाता हैय लेकिन जहां पुलिस दमन ही कानून बन जाये, उन्हें 'पुलिस स्टेट' कहा जाता है. दोनों स्थितियों में राजसत्ता की वैधता और औचित्य संकट में आ जाते हैं. पुलिस सुधार का मतलब है कि इन दोनों चरम के बीच का सामंजस्य और कानून का शासन जिसकी नींव पर लोकतंत्र टिकी है.

सम्पादकीय

बौद्धिक स्तर पर निबटने की जरूरत

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे स्वतंत्र पत्रकार को गिरफ्तार किया है, जो चीन सरकार के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स के लिए लेखन करते थे, भारत में सरकार से अधिमान्यता प्राप्त थे, लंबे समय तक विवेकानंद फाउंडेशन से भी जुड़े रहे. पुलिस की मानें तो, देश की सुरक्षा और सेना से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एक चीनी महिला की फर्जी कंपनी के माध्यम से उन्हें लाखों रुपये मिल रहे थे. भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महीनों से चल रहे विवाद का हमारी सेना ने अपने शौर्य और साहस से मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन चीन के साथ समस्या केवल सामरिक, व्यापारिक या डिजिटल नहीं है. चीन दुनियाभर में बौद्धिक स्तर पर ऐसा जाल फैला चुका है, जो कई स्तर पर उसकी सहायता करते है। दरअसल, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को नियंत्रित करती है. वहां कम्युनिस्ट पार्टी केवल हथियार या तकनीक से सेना को मजबूती नहीं देती, बल्कि कई मोर्चों पर निवेश और नियोजन भी करती है, जिससे उनकी सेना को कई जगह बिना लड़े ही जीत मिल जाती है. इसके लिए उसने सूचना तंत्र तैयार करने, जानकारी एकत्र करने और सहूलियत के हिसाब से उसे दुनिया में प्रचारित करने का काम भी किया है. दूसरे शब्दों में, तो यह धारणाओं की लड़ाई का प्रबंधन है.

नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, गुओयानहुआ के एक चीनी प्रोफेसर ने साइकोलॉजिकल वारफेयर नॉलेज नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, श्जब कोई दुश्मन को हराता है, तो यह महज दुश्मन को मारना या जमीन के एक टुकड़े को जीतना नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप से दुश्मन के दिल में हार का भाव स्थापित करना होता हैघ्श् युद्ध के मैदान के बाहर प्रतिद्वंद्वी के मनोबल को कम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध के मैदान में. जब से शी जिनपिंग ने चीन पर पूरी तरह नियंत्रण किया है, तब से वह न केवल अपने देश में बल्कि अन्य देशों में भी मीडिया को नियंत्रित करने पर बहुत काम कर रहे हैं. सभी जानते हैं कि चीन में अखबार, टीवी, सोशल मीडिया से लेकर सर्च इंजन तक सरकार के नियंत्रण में है. वहां का प्रकाशन उद्योग भी सरकार के कब्जे में है. हर वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में लगने वाला पेइचिंग पुस्तक मेला दुनियाभर के बड़े प्रकाशकों को आकर्षित करता है. वहां चीन के फॉरेन पब्लिशिंग डिपार्टमेंट का असली उद्देश्य अपने यहां की पुस्तकों के अधिक से अधिक राइट्स बेचना होता है. बीते दस वर्षों में अकेले दिल्ली में चीन से प्राप्त अनुदान के आधार पर सैकड़ा भर चीनी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हुआ. भारत-चीन के विदेशी विभाग भी ऐसी ही अनुवाद परियोजना पर काम कर रहे हैं. दिल्ली के कई निजी प्रकाशक चीनी पुस्तकों के अनुवाद छापकर मालामाल हो रहे हैं. इस तरह चीन दुनियाभर के जनमत निर्माताओं, पत्रकारों, विश्लेषकों, राजनेताओं, मीडिया हाउसों और लेखकों-अनुवादकों का समूह बनाने में भारी निवेश कर रहा है, जो अपने-अपने देशों में चीनी हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील और इच्छुक हैं. इसके पीछे असली एजेंडा शांति और युद्ध के समय चीन की भव्यता, ताकत, क्षमता को दूसरे देशों में प्रसारित करना है. ऑस्ट्रेलिया से संचालित होनेवाली कई चीनी कंपनियां, भारत जैसे देशों में होनेवाले एकेडमिक सेमिनारों में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं, जो सेमिनार में पढ़े गये शोध पत्रों को हासिल करते हैं और चुपचाप वापस चले जाते हैं. ऐसे शोध का वे अपने यहां विस्तार से अध्ययन करते हैं और उसके उत्पादों का पेटेंट भी हासिल कर लेते हैं. चीनी सरकार भारत सहित कई देशों में मीडिया में निवेश के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है. हाल ही में, चीन ने विदेशी मीडिया प्रकाशनों में विज्ञापन स्थान की खरीद के माध्यम से भारी निवेश किया है. चीन मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीकी देशों के विदेशी पत्रकारों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम भी चलाता हैघ्, जिसके तहत प्रतिवर्ष सौ पत्रकारों को अपने देशों में चीनी विचारों का प्रचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. पेइचिंग विश्वविद्यालय सहित कई जगह हिंदी के कोर्स हैं, जहां छात्रों का कार्य होता है नियमित भारतीय अखबार पढ़ना, उसमें चीन के उल्लेख को अनुदित करना, उसके अनुरूप सामग्री तैयार करना. टीवी बहस में शामिल होनेवाले कई सेवानिवृत सैन्य अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने कभी लेह-लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में सेवा नहीं दी. असल में ऐसे अधिकारी या लेखक किसी हथियार एजेंसी या अन्य उत्पाद संस्था के भारतीय एजेंट के तौर पर काम करते हैं. उनकी सेवा शर्तों में भारतीय सैन्य स्थिति का अनुमान, उसकी सतही व्याख्या, किसी हथियार या उपकरण की आवश्यकता के बारे में बातें करना, अन्य देश के वैसे ही उपकरण की तुलना में चीनी उत्पाद को बेहतर बताना, आदि का उल्लेख होता है.

लोगों का विश्वास जीतना और फिर उनमें अपने विचार संप्रेषित करना चीन का बौद्धिक युद्ध कौशल है. सैन्य स्तर पर हम चीन से निश्चित ही निबट लेंगे, लेकिन आर्थिक और बौद्धिक स्तर पर निपटने के लिए हमें अभी और तैयारी करनी होगी।

भारत में कोरोना का प्रसार दुनिया में सबसे तेज

कोविद -19 पर नकारात्मक खबरों से बचने के लिए विपक्षी दल मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन पार्टियों से ज्यादा, खासकर राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से इस मसले पर पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अब वैश्विक पेशेवर संस्थाओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 26 सितंबर के अपने संपादकीय में सह-समीक्षित मेडिकल जर्नल लैंसेट ने भारत सरकार की नीति के खतरों को उजागर किया है। यह कहता है कि भारत में सरकार वर्तमान स्थिति को बहुत अधिक सकारात्मक रूप से प्रचारित कर रही हैं। यह न केवच सच्चाई को झुठलाना है, बल्कि इसके कारण महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल भी बाधित हो रही है। अवास्तविक दावों को लागू करना या नकारात्मक रूप से नकारात्मक रिपोर्ट करने में विफल रहना, सार्वजनिक और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बीच अनिश्चितता पैदा करता है, लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने या सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों को गंभीरता से लेने से हतोत्साहित करता है। संपादकीय में यह चेतावनी दी गई है। लैंसेट का कहना है कि भारत को महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनुसंधान और राष्ट्र का नेतृत्व करने में विशेषज्ञता हासिल है। इन विशेषताओं को भुनाने के लिए, देश के नेताओं को वैज्ञानिक साक्ष्य, विशेषज्ञ टिप्पणी और अकादमिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, न कि झूठी आशावाद प्रदान करना चाहिए।

महामारी की शुरुआत में मजबूत प्रतिक्रिया के बावजूद, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूर्ण संख्या में कोविद-19 का दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता प्रकोप है, जिसने 6 मिलियन से अधिक संक्रमणों की अब तक पुष्टि हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर मामले की संख्या में निरंतर नाटकीय वृद्धि के बावजूद भी प्रतिबंध हटाए जाने के साथ, राज्यों के बीच और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच चिह्नित मतभेदों के साथ रोग के प्रसार का पैटर्न बारीक और जटिल है। उदाहरण के लिए, भारत के उत्तर में कोलकाता और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे शहरों में शुरू में प्रकोप अपेक्षाकृत कम था, जबकि मजबूत अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के साथ दिल्ली पहली लहर में सबसे आगे था। फिर भी, भारत स्पष्ट रूप से एक खतरनाक अवधि का सामना कर रहा है। लैंसेट ने नोट किया कि कैसे लॉकडाउन ने कई लोगों के लिए एक समानांतर संकट पैदा कर दिया क्योंकि आय नाटकीय रूप से गिर गई, भूख बढ़ गई, और कई प्रवासी श्रमिक लंबी दूरी के घर चले गए। महामारी के प्रकोप से पहले ही जीडीपी कम हो रहा था, लेकिन अप्रैल से जून की तिमाही में साल पर लगभग 25 प्रतिशत का संकुचन भारत को आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक बना सकता है। जैसे-जैसे राज्यों में इसका प्रकोप शहर के छोटे इलाकों और गांवों तक फैलता गया है, स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में पहले से मौजूद असमानताएं तेजी से प्रासंगिक हो गई हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है, और कुछ छोटे निजी अस्पतालों ने उपकरण की कमी, विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, तेजी से बढ़ते मामले की संख्या, प्रतिबंधों की निरंतर छूट के साथ, झूठी आशावाद के साथ घिनौनापन का माहौल पैदा कर रहा है जो मास्क और शारीरिक गड़बड़ी जैसे गैर-दवा हस्तक्षेपों के प्रभावी उपयोग को कमजोर करता है। पत्रिका ने नोट किया है कि भारत में महामारी समाप्त होने से अभी काफी दूर है और इसका खतरा उस समय तक बना रहेगा, जब तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का उपयोग नहीं किया जाता है और इसका पालन किया जाता है। मोदी सरकार को लगता है कि निराशावाद, नकारात्मकता और अफवाह के प्रसार से निपटना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक समाचारों से बचने के लिए, और झूठा आश्वासन देने के लिए पेशेवर वैज्ञानिकों पर सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। भारत में कई पेशेवर वैज्ञानिक संगठनों द्वारा ऐसा महसूस किया गया है। लैंसेट पत्रिका ने इसका खुलासा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक सबूतों से भटकाने के लिए कहा जा रहा है, जो सबसे खराब राजनीति से प्रेरित और सबसे बेहतर आशावादी है। पत्रिका, वास्तव में, आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव के उस पत्र का हवाला देती है, जिसमें कहा गया था कि आईसीएमआर ने स्वतंत्रता दिवस के बाद एक कोरोनोवायरस वैक्सीन शुरू करने की परिकल्पना की थी, जो ज्यादातर चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा अवास्तविक माना गया। और यह अंततरू झूठ भी साबित हुआ। रिपोर्ट के बीच अपर्याप्त सबूतों के बावजूद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के साथ उपचार का समर्थन करने के लिए आईसीएमआर को भी दोषी माना गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के डेटा को एक वैज्ञानिक पेपर से हटा दिया गया था। कोविद के मामलों और मौतों पर आंकड़ों की पारदर्शिता, विशेष रूप से मामले की घातक दर को कम करने वालों से पूछताछ की गई है।

शाहीन बाग की दादी के रूप में हमारे साथ गांधी मौजूद होते हैं

कैसी गजब बात है कि महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष का समापन होते-होते सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से निकलने वाली पत्रिका श्टाइमश् में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की जो फेहरिस्त छपी है, उसमें जहां एक ओर हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शामिल किया गया है, वहीं नागरिकता कानूनों के खिलाफ छेड़े गये देशव्यापी आन्दोलन की बुजुर्ग नायिका बिलकिस की भी शिरकत है। यह आजादी के आंदोलन के दौरान एक बूढ़े महात्मा और शक्तिशाली ब्रिटिश एंपायर से टकराने की तस्वीर जैसा है। फर्क यह है कि तब बिदेसिया सरकार थी जिससे देश को आजाद करने की लड़ाई बापू लड़ रहे थे, तो आज स्वदेशी सरकार है लेकिन उसका कामकाज का ढंग वैसा ही है- शोषणकारी, दमनात्मक और गैर लोकतांत्रिक। 2014 में बनी सरकार जहां लोगों की नागरिक आजादी छीनकर उन्हें कमजोर प्रजा बनाने पर आमादा है ताकि वे प्रतिरोध न कर सकें, तो दूसरी तरफ शाहीन बाग आंदोलन की भावना गांधी निर्मित नागरिक चेतना पर आधारित है।गांधीजी ने जिन उद्देश्यों को लेकर लड़ाई की थी, वह स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व की थी और तरीका अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था। शाहीन बाग की लड़ाई इन्हीं दो आजमाये व सफल हुए तरीकों से लड़ी गई है। उसे खत्म करने के लिये सरकार और उसके समर्थकों ने वैसे ही अनेक हथकण्डे अपनाये जैसे आजादी की लड़ाई के दौरान उठे विभिन्न आंदोलनों को कुचलने के लिये देखे गये थे। हिंसा के कारण 1920 का असहयोग आंदोलन समेटा गया तो दुनिया और बरतानियों को लगा कि यह खत्म हो गया है। ऐसे ही, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन करीब दो साल बाद समाप्त हुआ तो भी लोगों ने सोचा कि अब भारत कभी स्वतंत्र नहीं होगा। 1920 से 1942 और 1942 से 1947 के दोनों कालखंडों में बापू चाहे खामोश नजर आ रहे थे लेकिन वे आंदोलन की भावना को मजबूत कर रहे थे। इन दोनों अवधियों में गांधी ने अनेक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन खड़े किये थे जिनका उद्देश्य भारत की सिर्फराजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक चेतना को मजबूत करना ही नहीं था वरन राष्ट्रीय चेतना और मानवीय गुणों का विकास भी करना था। भारत को आजादी मिलते ही महात्माजी तो चल बसे थे, पर जितने भी दिन रहे, वे प्रतिरोध के ही प्रतीक रहे- 14 अगस्त, 1947 तक अंग्रेज बहादुर और 15 अगस्त, 1947 से 30 अक्टूबर, 1947 तक इंसानी कमजोरियों के विरोध में। कुल जमा, हमारी आंखों और मनों में बापू की जो तस्वीर है वह एक विनम्र लड़ाके की है, जो ताकतवर के खिलाफ लड़ता है तथा कमजोर के साथ खड़ा होता था। कुछ लोगों के सिद्धांत व जीवन दर्शन उनके साथ ही चले जाते हैं, तो कुछ के जीवन उनके जाने के बाद भी रास्ता दिखलाने का काम करते हैं। गांधी बाद वाली श्रेणी में आते हैं, जो अपना वैचारिक डीएनए शाहीन बाग जैसे सत्याग्रहों में मौजूद लोगों में चुपचाप बराबर सरकाते रहते हैं। बिलकिस दादी गांधी की उसी विरासत का हिस्सा हैं, जो दुष्प्रचारियों द्वारा इन आंदोलनकारियों की पांच-पांच सौ रुपये के भाड़े वाले कार्यकर्ताओं, बिरयानी के लिये जुटने वालों और धंधेवालियों की छवि बनाने के बावजूद विचलित नहीं होतीं। इस उम्र में जब लोग ईश्वर-अल्लाह के नाम-जाप में जुट चुके होते हैं, बिलकिस व उनकी जैसी सैकड़ों महिलाएं अपनी नागरिक चेतना का देश भर के चौक-चौराहों पर जगराता करती हैं। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों का दमन तो केवल अपनी पुलिस-फौजों के बल पर ही किया था, परन्तु शाहीन बागवालियों का सामना पुलिस के साथ पिस्तौलें लहराते और लाठियां भांजते सत्ता के पिठ्ठुओं से भी हुआ है। गांधी की आत्मा इसलिये बिलकिस जैसी महिलाओं के जरिये जमीन पर उतर आती है क्योंकि गांधी प्रणीत आंदोलनों की ही तरह शाहीन बाग अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर खड़ा है। ऐसे सत्याग्रह कितने समय तक चलते हैं, सफल होते हैं या नहीं- यह महत्वपूर्ण कतई नहीं होता। उनके कुचल दिये जाने या बंद होने के बाद भी उनकी नैतिक उपस्थिति बराबर बनी रहती है और वे हमारी नागरिक चेतना के हिस्से बने रहते हैं। इसलिये श्टाइमश् पत्रिका चाहे जितना अपने मुल्क के हितों का ख्याल रखकर पत्रकारिता करे, पर शाहीन बाग आंदोलन को चलाने वाले दो मूलभूत तत्वों- अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता को पूरी दुनिया की तरह उसने मान्यता दी है। विरोधी विचारधाराओं की सरकारें एवं उनके समर्थकों के बार-बार उकसाने और दमन करने के बावजूद इस देशव्यापी आंदोलन ने अहिंसा-धर्मनिरपेक्षता का दामन नहीं छोड़ा। सत्याग्रही गांधी का इन्हीं तत्वों पर बल था, जो उन्होंने अपने जीवन में सतत उतारा है। अमेरिकी पत्रिका की संतुलन साधने की कवायद देखिये कि उन्होंने एक ओर तो जनविरोधी सत्ता के प्रतिनिधि बन चुके मोदी को छापा है तो वहीं दूसरी ओर इस प्रवृत्ति को चुनौती देने वाले आंदोलन के प्रतिनिधि चेहरे को भी, जो गांधी की ही तरह एक बुजुर्ग है पर जीवन दृष्टि में आधुनिक है, शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन इरादों में बुलन्दय और निहत्थी तो है पर नागरिक चेतना व आत्मिक रूप से सशक्त। टाइम की टाईमिंग यह भी है कि इसका प्रकाशन ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत में निरंकुश की तरह सरकार नोटबंदी व जीएसटी जैसे सनकपूर्ण फैसलों से अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है, तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को दीवाली सेल की तरह औने-पौने भावों में अपने मित्र उद्योगपति-व्यवसायियों को दे रही है, मुक्त हृदय से विदेशी पूंजी को आमंत्रित कर रही है, उद्योग-धंधों को चौपट कर चुकी है, लघु व ग्रामोद्योगों का सफाया हो चुका है, व्यवसाय बन्द होने से करोड़ों बेरोजगार हो गये हैं, जीडीपी -24 तक का गोता लगा चुकी है, कोरोना में लोग संक्रमण व भूख से मर रहे हैं, सरकार फंड बनाकर एकत्र पैसों का हिसाब देने से इंकार कर रही है, छात्र-युवा निराश हैं, नागरिकों की नकदी खत्म हो गई है, किसानों को अशक्त करने के लिये कृषि कानूनों के जरिये न्यूनतम समर्थन मूल्य व शासकीय मंडियों को समाप्त किया जा रहा है, उनकी फसलों के अधिक दाम मिलने के नाम पर कारपोरेट जगत को समृद्ध करने की योजना बनाई जा रही है, निजी खरीदारों के साथ दामों को लेकर होने वाले विवादों के निपटान हेतु खेतिहरों के लिये कोर्ट के रास्ते बन्द किये जा रहे हैं और श्रमिकों और मेहनतकशों की नौकरियां आसानी से छीने जाने वाले कानून श्रम सुधारों के नाम पर लाये जा रहे हैं। कोरोना काल में हमने जिस प्रकार से लोगों की लाचारी और सत्ता की असंवेदनशीलता देखी है, वह हमें गुलाम भारत की दुर्दशा की याद दिलाती है। ऐसे में बिलकिस जैसे नागरिकों द्वारा बुनियादी हकों के लिये आंदोलनों की जरूरत है। वैसे हमारी सरकार भली-भांति जानती है कि जिन पर हर तरह के अत्याचार किये जा सकें वैसे कमजोर नागरिकों से ही फैलादी पकड़ वाले राज्य बनते हैं, इसलिये ये जनविरोधी कदम उठाये जा रहे हैं। इसके विपरीत, गांधीजी राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप और शक्तिशाली नागरिक के पक्षधर थे। सोचना तो यह भी होगा कि पत्रिका ने इस समय दादी को प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल क्यों किया, जबकि शाहीन बाग आंदोलन तो चार माह पहले ही कोविड-19 के चलते देश भर में समेट लिये गये हैं। संभवतरू पत्रिका जानती है कि नागरिक आंदोलन इतनी आसानी से नहीं मरते, चाहे वे कुछ काल के लिये स्थगित जरूर हो सकते हैं। दुनिया भर में इस तरह के कई आंदोलन उदाहरणों के रूप में मिल जायेंगे। ऐसे ही, कोरना के कारण यह आंदोलन फिलहाल स्थगित है पर यह अंदर-अंदर से जीवित है जो मौका पड़ने पर जाग उठेगा। गांधीजी की तरह धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। तब तक ऊर्जा बटोरनी है, रचनात्मक बने रहना है और आशा को बनाये रखना है। श्टाइमश् पत्रिका कहती है कि श्सरकार उसकी बनती है जिसका बहुमत हो परन्तु लोकतंत्र उसकी भी बात करता है जिसने बहुमत पाने वाले को वोट नहीं दिया। बिलकिस सामाजिक रूप से ही अल्पसंख्यक नहीं बल्कि वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में भी अल्पसंख्यक बन चुकी विवेक, अंतरात्मा और लोकतंत्र की आवाज है, जिसने सरकार बनाने में मोदी व उनकी पार्टी के खिलाफवोट किया होगा। बापू भी हर-हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ थे। आजादी के कुछ पहले से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद तक तो और भी कसकर।

सार समाचार ....

मुस्तफिजुर को आईपीएल 2020 में नहीं खेल पाने का मलाल

नईदिल्ली एजेंसी। बांग्लादेश को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलनी थी और इसी के चलते तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आइपीएल 2020 में खेलने की अनुमति नहीं मिली। अब यह सीरीज कोरोना के रद हो गई है। इसके चलते मुस्तफिजुर को टूर्नामेंट में नहीं खेल पाने का अफसोस हो रहा है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में नहीं खेल पाने पर अफसोस हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस तेज गेंदबाज को टूर्नामेंट में खेलने के लिए नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। बांग्लादेश को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलनी थी और इसी के चलते उन्हें आइपीएल में खेलने की अनुमति नहीं मिली। अब कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद करना पड़ा। इसके बाद मुस्तफिजुर ने कहा कि अगर बीसीबी को पता था कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को स्थगित कर दिया जाएगा, तो उन्हें मुझे आइपीएल के लिए एनओसी देना चाहिए थे। लेकिन जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है। आइपीएल में खेलकर मैं 1 करोड़ बीडीटी (बांग्लादेश टका) कमा सकता था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीमों ने उनके अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले बीसीबी ने चोट की समस्या के कारण 2015-16 में पाकिस्तान सुपर लीग (क्र्रु) में हिस्सा लेने के लिए मुस्तफिजुर को एनओसी देने से इनकार कर दिया था। टूर्नामेंट न खेलने से हुए नुकसान के लिए बोर्ड ने उन्हें 30 लाख बीडीटी (बांग्लादेश टका) दिया था। हालांकि, बीसीबी ने साफ कर दिया है कि इस बार बोर्ड ऐसा नहीं करेगा। सोमवार को बांग्लादेश का श्रीलंका दौरा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों के तहत 14 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन पर राजी नहीं हुए। बांग्लादेश को शुरुआत में तीन टेस्ट मैचों के लिए जुलाई-अगस्त में श्रीलंका का दौरा करना था लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे टाल दिया गया था। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को 27 सितंबर से श्रीलंका के दौरे पर जाना था, जिसमें पहला टेस्ट 23 अक्टूबर से खेला जाता।

केएल राहुल और मंयक अग्रवाल मेंऑरें ज कैप के लिए कड़ी टक्कर

नईदिल्ली एजेंसी। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में पंजाब का बोलबाला है। पहले स्थान पर किंग्स के कप्तान राहुल है तो दूसरा स्थान मयंक ने हासिल कर लिया है। चेन्नई के फाफ डु प्लेसिस तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं तो संजू सैमसन ने चौथा स्थान हासिल किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हर मैच में लगभग बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए हैं। पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने सीजन का पहला शतक जमाया तो मयंक ने दूसरी सेंचुरी जड़ दी। हर साल जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाता है इसके सिर पर ऑरेंज कैप सजता है। राजस्थान और पंजाब के बीच हुए मुकाबले के बाद केएल राहुल रन बनाने के मामले में सबसे आगे हो गए हैं और उनके पास ही इस वक्त यह कैप वापस आ गई है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में पंजाब की टीम का बोलबाला है। पहले स्थान पर किंग्स के कप्तान राहुल है तो दूसरा स्थान मयंक ने हासिल कर लिया है। चेन्नई के फाफ डु प्लेसिस तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं तो संजू सैमसन ने चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं स्टीव स्मिथ अब पांचवें नंबर पर आ गए हैं। राजस्थान के खिलाफ अर्धशतक जमाते हुए ऑरेंज कैप पर केएल राहुल ने कब्जा जमा लिया है। 3 मैचों में राहुल ने कुल 222 रन बनाए हैं जिसमें 132 रन की सर्वाधिक रनों की पारी भी शामिल है। राहुल ने 23 चौके और 9 छक्के लगाए हैं। पंजाब के ही मयंक अग्रवाल दूसरे नंबर पर काबिज हैं। 2 मैचों में 221 रन बनाने वाले इस बल्लेबाज ने राजस्थान के खिलाफ शानदार शतक जमाया। उनका स्ट्राइक रेट 170 का हो गया है और वह कप्तान राहुल से महज एक रन ही पीछे हैं।

राजस्थान रॉयल्स व केकेआर दोनों फॉर्म में, किसकी होगी जीत कहना मुश्किल

अबुधामी | एजेंसी।

12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स व कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जोरदार टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। केकेआर ने अपना पिछला मैच जीता था तो वहीं राजस्थान ने अपने पहले दोनों मुकाबले जीते हैं और इस टीम ने पंजाब के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर चेज किया था। वहीं पहले मैच में धौनी की सीएसके को मात दी थी। स्मिथ की कप्तानी वाली इस टीम को छुपा रुस्तम माना जा रहा था और इस टीम ने खुद को अब तक तो साबित किया है। केकेआर की बात करें तो इस टीम में शानदार बल्लेबाज हैं और टीम की गेंदबाजी भी काफी अच्छी है। पिछले मैच में इस टीम ने बड़ी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया था और टीम को मनोबल काफी उंचा है। ऐसे में ये बात कहना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी, लेकिन दोनों के बीच टक्कर जोरदार होगी ये तय है। फॉर्म में राजस्थान के बल्लेबाज राजस्थान की इन सफलताओं में संजू सैमसन और राहुल तेवतिया का योगदान अहम रहा है, जो अब तक स्टार खिलाड़ियों पर भारी पड़े हैं। हरियाणा के ऑलराउंडर तेवतिया ने किंग्स इलेवन के खिलाफ पिछले मैच में 31 गेंदों पर 53 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया था। तेवतिया ने एक समय 19 गेंदों पर सिर्फ आठ और फिर 23 गेंदों पर 17 रन बनाए थे, लेकिन अचानक ही उनके अंदर का आक्रामक बल्लेबाज जाग उठा और उन्होंने तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में पांच छक्के लगाकर मैच का नक्शा बदल दिया। वहीं, केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने लगातार दो अर्धशतक जमाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 214.86 है। इससे उन्होंने भारतीय टीम में विकेटकीपर कप्तान स्टीव स्मिथ ने भरोसमंद की भूमिका निभाई है। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज जोस बटलर से टीम को धमाकेदार पारी का इंतजार है। कोलकाता को रसेल व मोर्गन से उम्मीद = अगर केकेआर को रॉयल्स की बराबरी करनी है या उससे आगे निकलना है तो उसके सबसे बड़े स्टार आंद्रे रसेल और इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मोर्गन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मोर्गन और रसेल को अभी तक कम मौके मिले हैं, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में पांचवें और छठे नंबर पर उतारा गया। केकेआर का टीम प्रबंधन इस मैच में उन्हें ऊपरी क्रम में उतार सकता है। केकेआर को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस से शिकस्त मिली, लेकिन दूसरे मैच में उसने सनराइजर्स हैदराबाद की गलतियों का फायदा उठाकर अच्छी वापसी की। प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के नाबाद अर्धशतक और मोर्गन की तूफानी पारी से केकेआर ने दो ओवर शेष रहते ही 145 रन के लक्ष्य को हासिल कर दिया था। अब तक ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं और किसी भी टीम ने ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। सीएसके की बात करें तो इस टीम ने भी अब तक कुल 3 मैच खेले हैं जिसमें टीम को 2 मैच में हार मिली है और एक में जीत हासिल हुई थी जो उसने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली थी। सीएसके को अब तक इस लीग में तीन मैचों में 2 अंक हैं और वो मंगलवार तक अंत तालिक में सबसे नीचे थी। एम एस धौनी की टीम का ये हाल होगा ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। हालांकि टीम को अभी आगे और मुकाबले खेलने हैं, लेकिन मौजूदा हालात में क्रिकेट फैंस इस टीम का खूब मजाक बना रहे हैं। इस वक्त अंक तालिका में सबसे उपर राजस्थान की टीम है जिसने दोनों मैच जीते हैं और उसके चार अंक है। तो वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली की टीम है जिसके तीन मैचों में दो जीत के साथ 4 अंक है। वहीं बैंगलोर के भी तीन मैचों में 4 अंक ही है। हालांकि चेन्नई के अलावा अब तक की अंकतालिक में पंजाब, मुंबई, हैदराबाद व कोलकाता के दो-दो अंक हैं, लेकिन वो सभी रन रेट के मामले में सीएसके से आगे हैं। हैरानी की बात ये है कि सीएसके को इस बात जीत के दावेदारों में देखा जा रहा है, लेकिन टीम के प्रदर्शन ने अब तक तो निराश ही किया है। सीएसके का अगला मैच शुक्रवार को एसआरएच के साथ होगा।

कोलकाता नाइटराइडर्सः दिनेश कार्तिक (कप्तान), आंद्रे रसेल, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, नितिश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, शिवम मावी, शुभमन गिल, सिद्धेश लाड, सुनील नरेन, पैट कमिंस, इयोन मोर्गन, वरुण चक्रवर्ती, टॉम बेंटन, राहुल त्रिपाठी, क्रिस ग्रीन, एम सिद्धार्थ, निखिल नाइक, अली खान।

राजस्थान रॉयल्स : स्टीव स्मिथ (कप्तान), जोस बटलर, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह, ओशाने थॉमस, एंड्रयू टाई, डेविड मिलर, टॉम कुर्रन, अनिरुद्ध जोशी, श्रेयस गोपाल, रियान पराग, वरुण आरोन, शशांक सिंह, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर, मयंक मार्कंडेय।

05 मैच खेले गए हैं इस आइपीएल में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। इन पांचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं। इनमें सुपर ओवर के दोनों मुकाबले भी शामिल हैं।

डेविड वार्नर ने बतौर कप्तान आइपीएल में हासिल किया खास मुकाम

आईपीएल 2020 सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर आइपीएल में बतौर कप्तान 50 मैच खेलने वाले नौवें खिलाड़ी बन गए। इस मैच में उन्होंने 45 रन की पारी खेली तो वहीं टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज बेयरस्टो ने 53 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने दिल्ली कैपटिल्स के खिलाफ जैसे ही मैदान पर कम रखा एक खास मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया। आइपीएल में कप्तान के तौर पर डेविड वार्नर ने दिल्ली के खिलाफ अपना 50वां मैच खेला। वार्नर से पहले आइपीएल में 8 कप्तानों ने ये उपलब्धि पहले ही हासिल कर रखी है। आइपीएल में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी जिन्होंने अब तक कुल 177 मैच खेले हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर गौतम गंभीर हैं जिन्होंने इस लीग में बतौर कप्तान कुल 129 मैच खेले थे। तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने कप्तान के रूप में अब तक कुल 113 मैचों में खेला है। रोहित शर्मा 107 मैचों के साथ चौथे स्थान पर हैं तो एडम गिलक्रिस्ट 74 मैचों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। आइपीएल में कप्तान के तौर पर 50 या उससे ज्यादा मैच कप्तान के तौर पर खेलने वाले कुल 9 खिलाड़ी अब तक हैं। इसमें 6 भारतीय खिलाड़ी हैं जबकि तीन विदेशी खिलाड़ी हैं। अब वार्नर तीसरे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान अपना 50वां मैच आइपीएल में खेला है। वार्नर ने बतौर कप्तान अपने 50वें मैच में 33 गेंदों में 3 चौके व 2 छक्कों की मदद से 45 रन की पारी खेली तो वहीं टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों पर 53 रन बनाए। वहीं केन विलियमसन ने 26 गेंदों पर 41 रन बनाए और इन खिलाड़ियों के प्रयास से हैदराबाद की टीम ने दिल्ली के खिलाफ पहली पारी में 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए। वहीं कप्तान के तौर पर उन्होंने अपना 50वां मैच जीत लिया। इस मैच में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन बना पाई और हैदराबाद ने मैच 15 रन से जीत लिया।

संन्यास के बाद धौनी फिल्मी दुनिया में रखेंगे कदम

नईदिल्ली एजेंसी। धौनी की इंटरटेंमेंट मीडिया कंपनी ने पिछले साल अगस्त में के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। इसमें पूर्व कप्तान धौनी के सफर को ही दिखाया गया था। इसका निर्देशन जाने माने निर्देशक कबीर खान ने किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने पिछले महीने 15 अगस्त को ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद अब पूर्व कप्तान फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। पिछले साल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने वाले धौनी अब एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज लाने का विचार कर रहे हैं। धौनी की इंटरटेंमेंट मीडिया कंपनी ने पिछले साल अगस्त में इसमें पूर्व कप्तान धौनी के सफर को ही दिखाया गया था। इसका निर्देशन जाने माने निर्देशक कबीर खान ने किया था। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स के वापसी को दर्शाया गया था। दो साल के बैन के बाद टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी की थी और खिताब भी जीता था। पीटीआइ के मुताबिक अब धौनी की इंटरटेंमेंट कंपनी एक वेब सीरीज को निर्माण करने जा रही है।

श्रेयस अय्यर की बात को काटते हुए कोच रिकी पोटिंग ने बताया दिल्ली की हार का कारण

नई दिल्ली , एजेंसी।

दिल्ली कैपिटल्स को आइपीएल 2020 के अपने तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 15 रन से हार का सामना करना पड़ा। ये दिल्ली का तीसरा मैच था और ये टीम अपने पहले दो मुकाबले जीत चुकी थी। तीसरे में उसे हार मिली। टीम की इस हार के बाद कोच रिकी पोंटिंग ने बताया कि टीम की हार की मुख्य वजह क्या रही। वहीं रिकी पोंटिंग ने साफ कर दिया कि पिच में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी और सच तो ये रहा कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। उनके मुताबिक हैदराबाद की टीम ने उनके टीम के मुकाबले हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए और इसके जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 के स्कोर तक ही पहुंच पाई। पोंटिंग से पूछा गया कि कंडीशन की वजह से मैच के रिजल्ट पर कोई असर हुआ तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद की टीम रणनीति के मामले में उनकी टीम से बेहतर साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कंडीशन ज्यादा अलग थे। रिकी ने कहा कि यहां का मैदान बड़ा था साथ ही स्क्वायर बाउंड्री भी बड़ी थी, लेकिन सच तो ये है कि अंत में हैदराबाद ने हमें पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर पाए साथ ही बल्लेबाज कोई बड़ी साझेदारी नहीं निभा पाया। हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी की साथ ही कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर भी बनाया। हम ऐसा नहीं कर पाए और इसी ने अंतर पैदाा किया। पोंटिंग ने दिल्ली के बारे में कहा कि अगर कोई एक बल्लेबाज 60 या 70 का स्कोर करता तो हम मैच जीत सकते थे। कप्तान श्रेयस ने कहा था कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान गेंद असमान गति से आ रही थी तो वहीं पोंटिंग ने कहा कि हमारी बल्लेबाजी के वक्त हालात और बेहतर थे साथ ही ओस भी थी। हम कोई बहाना नहीं बना सकते सच तो ये है कि उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छा खेला।

मोहम्मद शमी और रबादा में कड़ी टक्कर, किसके सिर पर सजी है पर्पल कैप

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 11 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अब तक वैसे तो बल्लेबाजों का ही बोलबाला देखने को मिला है। दनदना रन बरसने के बाद भी गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज से सिर पर सजती है पर्पल कैप। इस वक्त दिल्ली के रबादा और पंजाब के शमी के बीच इसको लेकर जोरदार जंग चल रही है। दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबादा विकेट लेने के मामले में पहले नंबर पर चल रहे हैं। 3 मैच खेलकर उन्होंने अब तक कुल 7 विकेट हासिल किए हैं। इसमें 26 रन देकर 3 विकेट उनकी सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। पंजाब के खिलाफ दिल्ली की टीम को सुपर ओवर में रबादा ने शानदार गेंदबाजी कर जीत दिलाई थी। किंग्स इलेवन पंजाब के मोहम्मद शमी के पास पर्पल कैप थी जिसे रबादा ने हासिल कर लिया है। शमी ने भी रबादा के बराबर 7 विकेट हासिल किए है लेकिन बेहतर इकोनॉमी की वजह से वह दिल्ली के गेंदबाज के पीछे दूसरे स्थान पर हैं। शमी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन इस सीजन में 15 रन देकर 3 विकेट का रहा है। मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट को इस वक्त इस लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त है। 3 मैच खेलने वाले बोल्ट को खाते में 5 विकेट हैं। 30 रन देकर दो विकेट उनका अब तक का बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का प्रदर्शन अब तक इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन गेंदबाज सैम कुर्रन 5 विकेट लेकर चौथे नंबर पर हैं। तीन मैच खेलने वाले इस युवा गेंदबाज ने 7.33 की इकोनॉमी से रन दिए हैं इसी वजह से बोल्ट के बराबर विकेट लेने के बाद भी वह चौथे नंबर पर हैं।

बांग्लादेश का श्रीलंका दौरा चढ़ा कोरोना वायरस की भेंट

ढ़ाका| एजेंसी।

कोरोना वायरस महामारी का असर क्रिकेट पर लगातार जारी है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल का आयोजन बहुत सारी पाबंदियों के बीच हो रहा है, लेकिन कई छोटे देश अभी भी रिस्ल लेने से कतरा रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश का श्रीलंका दौरा टाल दिया गया। इस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज और एक सीमित ओवरो की सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। श्रीलंकाई टीम को बांग्लादेश की मेजबानी अक्टूबर के महीने में करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस दौरे को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले भी इस दौरे को कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा था। दरअसल, श्रीलंकाई सरकार बांग्लादेश के खिलाड़ियों को 14 दिन के क्वारंटाइन के समय में छूट देने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे में दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड को ये दौरान स्थगित करना पड़ा। बता दें कि आइसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत तीन मैचों की टेस्ट सीरीज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जुलाई-अगस्त में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे अक्टूबर-नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इस टेस्ट सीरीज के लिए अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार 27 सितंबर को बांग्लादेश की टीम को श्रीलंका दौरे पर जाना था, जहां 23 अक्टूबर से पहला टेस्ट खेला जाना था। श्रीलंका के स्वास्थ्य विभाग ने बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ियों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा था, जिसके लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं था। दोनों देशों के बीच इसको लेकर बात चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा था कि अगर श्रीलंका सरकार हमारे खिलाड़ियों के क्वारंटाइन के समय में छूट नहीं देती है तो टीम श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएगी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीजन की शुरुआत करेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम

नयी दिल्ली , एजेंसी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कोरोना वायरस के कारण ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के साथ करेगा। देश के क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को घरेलू सत्र का कार्यक्रम जारी किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने घोषणा की कि नवंबर में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की मेजबानी के बाद फरवरी में ऑस्ट्रेलिया, जबकि मार्च में बांग्लादेश की मेजबानी की जाएगी। सरकार ने अब तक शुरुआती दो टीमों को ही आने की इजाजत दी है, लेकिन एनजेडसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड वाइट को भरोसा है कि अन्य टीमों की मेजबानी को भी हरी झंडी मिल जाएगी। वाइट ने कहा कि पिछले छह या सात महीनों की अनिश्चितता और मुश्किलों को देखते हुए आज की घोषणा करते हुए मैं रोमांचित हूं। उन्होंने कहा, इन दौरों की मेजबानी दो कारणों से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड घरेलू सत्र की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 27 नवंबर को ईडन पार्क में खेलकर करेगा। अन्य दो मैच बे ओवल में 29 और 30 नवंबर को खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम इसके बाद दो टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी। पहला टेस्ट हैमिल्टन के सेडन पार्क में तीन दिसंबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में 11 दिसंबर से खेला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आएगी। तौरंगा में 26 दिसंबर से होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जो 18 दिसंबर से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज का आयोजन 22 फरवरी से सात मार्च के बीच किए जाने का कार्यक्रम है। न्यूजीलैंड के घरेलू सत्र का अंत बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के साथ होगा, जिसमें 13 से 28 मार्च के बीच तीन वनडे और इतने ही टी-20 मैच खेले जाएंगे।

पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

नई दिल्ली, देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इससे पहले डीजल के दाम में लगातार चार दिन तक कटौती हुई। कल डीजल आठ पैसे सस्ता हुआ था जबकि पेट्रोल के दाम आठ दिन से स्थिर हैं। पेट्रोल के दाम में आखिरी बार 22 सितंबर को सात से आठ पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। सितंबर माह में डीजल 2.94 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ । विश्व में कोरोना वायरस के कारण अभी तक कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तेल विपणन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन आयल के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 70.63 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। वाणिज्यिक नगरी मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 77.04 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा।

एलवीबी को खरीदेगा पीएनबी.....

● वर्ष 2003 में पीएनबी ने केरल के एक लघु निजी बैंक नेडुंगडी बैंक का अधिग्रहण कर लिया था। इस अधिग्रहण से पीएनबी को केरल के तेजी से बढ़ते बाजार में मौजूदगी दर्ज कराने में मदद मिली थी। हालांकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में पीएनबी की सीमित उपस्थिति है।

नई दिल्ली | एजेंसी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के संभावित अधिग्रहण के लिए तैयार रहने को कहा है। अगर क्लिक्स कैपिटल के साथ एलवीबी की प्रस्तावित बातचीत बेनतीजा साबित हुई तो उस सूरत में पीएनबी को आगे आना पड़ सकता है। आरबीआई ने पीएनबी के अलावा दूसरे सरकारी बैंकों को भी एलवीबी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कमर कसने को कह दिया है। पीएनबी के एक शीर्ष सूत्र के अनुसार शुक्रवार को एक के बाद एक घटनाओं ने पूरा मामला ही पलट दिया, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक को तैयार रहने के लिए कह दिया। सबसे पहले शेयरधारकों के एक समूह ने एलवीबी के सात निदेशकों के दोबारा चयन का प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके बाद बैंक ने रविवार को रोजमर्रा का परिचालन संभालने के लिए निदेशकों की एक समिति नियुक्त कर दी है। पीएनबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंक को दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को साथ लाने का पहले से ही अनुभव है। अधिकारी ने कहा, %ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंकों के विलय से

देश के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में पीएनबी की पैठ खासी बढ़ी है। पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बैंक को दक्षिण भारत में भी बड़े स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। हालांकि अधिकारी ने भी स्पष्ट कर दिया कि एलवीबी को लेकर फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ तय नहीं हो पाया है। अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि अब एलवीबी के अधिग्रहण से यह कमी संभवतः पूरी हो जाएगी। एलवीबी पर उस समय संकट में फंस गई जब इसके शेयरधारकों ने सांविधिक अंकेक्षक एवं शाखा अंकेक्षकों की नियुक्ति को अपनी मंजूरी नहीं दी। बैंक के शेयरधारक क्लिक्स के साथ विलय के खिलाफ थे। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई ने एलवीबी को मुश्किलों से उबारने के लिए इस वर्ष के शुरू में ऑडिटर की नियुक्त पर अपनी मुहर लगा दी थी। शेयरधारकों ने निदेशक नामित करने का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया। जिन शेयरधारकों ने निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव खारिज कर दिया, उनमें श्रेय कैपिटल और इंडियाबुल्स फाइनैंस शामिल थे। एलवीबी में श्रेय कैपिटल की 3.4 प्रतिशत और इंडियाबुल्स फाइनैंस की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पहले एलवीबी के साथ इंडियाबुल्स फाइनैंस के विलय की बात चल रही थी, लेकिन आरबीआई ने इसकी इजाजत नहीं दी। पिछले साल नवंबर में आरबीआई ने एलवीबी को उसके खिलाफ दूसरी इकाइयों से आने वाले दावों से संभावित नुकसान की भरपाई के लिए कुछ रकम अलग रखने के लिए कहा था।

एक नजर.....

केन्द्र ने पंजाब और हरियाणा में खरीदी 16420 टन धान

नई दिल्ली, केंद्र ने मंगलवार को कहा कि पंजाब और हरियाणा में किसानों से पिछले 72 घंटों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 31 करोड़ रुपये के 16,420 टन धान की खरीद की गई है, जबकि बाकी राज्यों में खरीद का काम अभी शुरू ही हुआ है। नवीनतम खरीद आंकड़ों के साथ, सरकार का लक्ष्य नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों को संदेश देना है कि उसका एमएसपी में खरीद को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है. पंजाब और हरियाणा और कई अन्य राज्यों में किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि खरीद का काम अब कॉर्पोरेट्स के हाथों में चला जायेगा और एमएसपी व्यवस्था की समाप्ति हो जायेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि खरीफ फसलों की आवक अभी शुरू हुई है और सरकार मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर वर्ष 2020-21 के धान जैसी खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है. पंजाब और हरियाणा में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में यह 28 सितंबर से शुरू हुई। अकेले पंजाब और हरियाणा में, 1,888 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कुल 31 करोड़ रुपये के लगभग 16,420 टन धान की खरीद की गई है. इसमें से हरियाणा में लगभग 3,164 टन धान खरीदा गया है, जबकि पंजाब में 1,443 किसानों से 13,256 टन धान खरीदी गई है. चालू वर्ष के लिए, सरकार ने धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड) 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए ग्रेड किस्म 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए 14.09 लाख टन खरीफ दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी है. बयान में कहा गया है कि पीएसएस के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य राज्यों के लिए भी मंजूरी दी जाएगी। पीएसएस, अधिसूचित फसल कटाई अवधि में मंडी कीमतों के एमएसपी से कम होने की स्थिति में लागू होती है. सरकार ने 29 सितंबर तक, अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से, एमएसपी पर 33 लाख रुपये के 46.35 टन मूंग की खरीद की है, जिससे तमिलनाडु के 48 किसानों को फायदा हुआ है. इसी प्रकार, कर्नाटक और तमिलनाडु में 52.40 करोड़ रुपये की 5,089 टन नारियल गरी (बारहमासी फसल) की एमएसपी पर खरीद की गई है जिससे 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं. बयान में कहा गया है कि कपास की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी।

सीरम बनाएगी 20 करोड़ कोविड टीके

नई दिल्ली, दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में टीका बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) अब भारत के साथ-साथ निम्न और मध्यम आमदनी वाले देशों के लिए 2021 में कोविड-19 टीका 3 डॉलर या लगभग 250 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से करीब 10 करोड़ टीके का अतिरिक्त उत्पादन करेगी। कंपनी द्वारा इस कीमत पर पेशकश किए जाने वाले टीकों की कुल तादाद 20 करोड़ होगी क्योंकि उसे बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से 15 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त फंड मिला है जो जोखिम की स्थिति के लिए होगा। यह घोषणा व्यावहारिक रूप से सीरम इंस्टीट्यूट, टीके के लिए वैश्विक गठबंधन गावी और बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच सहयोग को आगे बढ़ाएगी जो अगस्त की उस घोषणा के बाद की गई है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वह 250 रुपये की एक खुराक के हिसाब से 10 करोड़ खुराक का वितरण करेगी। इस साझेदारी का विस्तार अब ऐस्ट्राजेनेका टीके और नोवावैक्स के कोविड-19 टीकों के लिए 20 करोड़ तक कर दिया गया है। गेट्स फाउंडेशन अपने रणनीतिक निवेश कोष के माध्यम से गावी को जोखिम की स्थिति के लिए 15 करोड़ डॉलर तक का फंड देगा जिससे इस सहयोग के लिए कुल फंड की राशि 30 करोड़ डॉलर तक हो जाएगी। यह गावी-कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट (एएमसी) का एक हिस्सा है जो कोवैक्स केंद्र के भीतर की ही एक प्रणाली है। कोविड-19 टीकों के लिए कोवैक्स सुविधा केंद्र दरअसल गावी के समन्वय वाली एक पूल खरीद प्रणाली है जिसके माध्यम से कोवैक्स हरेक प्रतिभागी अर्थव्यवस्था तक टीके की समान पहुंच सुनिश्चित करेगा और इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा तैयार किए जा रहे।

वेदांता ने नहीं लिया हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड

● एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यह डिविडेंड अभी नहीं दिया गया, तो डीलिस्टिंग के बाद मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज के एमडी श्रीराम सुब्रमण्यन ने कहा, कंपनी बोर्ड को डिविडेंड वितरण नीति का सख्ती से पालन करना चाहिए

नयी दिल्ली | एजेंसी।

इस साल मई में हिंदुस्तान जिंक ने वेदांता को 4,500 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था. यह डिविडेंड अभी तक कंपनी के शेयरधारकों तक नहीं पहुंच सका है. बता दें कि वेदांता की डीलिस्टिंग की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विशेषज्ञों के अनुसार, डिविडेंड वितरण की स्पष्ट नीति होने के बावजूद वेदांता के शेयरधारकों को डिविडेंड न देने से अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की डीलिस्टिंग का भाव कम हो सकता है। कंपनी की डिविडेंड वितरण नीति के अनुसार, हिंदुस्तान जिंक से मिलने वाले पूरे डिविडेंड को इसके शेयरधारकों के बीच बांटा जाएगा. इस विषय में वेदांता को भेजे गए सवालो के जवाब कंपनी ने नहीं दिए। यदि वेदांता डिविडेंड निवेशकों को देती तो

निवेशकों को प्रति शेयर 12.18 रुपये का डिविडेंड मिलता. बुधवार को कंपनी के शेयर 138 रुपये के भाव के आसपास कारोबार कर रहे थे। डिविडेंड रोकने के पीछे की वजह बताते हुए वेदांता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, समूह में वित्तीय शिथिलता की जरूरत है. बता दें कि वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक की 65 फीसदी हिस्सेदारी है। स्टेकहोल्डर्स एम्पापरमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ जेएन गुप्ता ने पूछा, क्या वेदांता का बोर्ड डिविडेंड भुगतान पर फैसला ले सकता है, जब समूह की अलग-अलग कंपनियों की वित्तीय स्थिति और शेयरधारक भिन्न हैं? गुप्ता ने कहा, कंपनी स्वेच्छा से डीलिस्ट हो रही है और कंपनी बोर्ड ने प्रमोटर्स की मदद की है कि वे डीलिस्टिंग की कीमत को नीचे ला सके. इसी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान जिंक से आए डिविडेंड का भुगतान नहीं किया, जिसके जरिए प्रमोटर्स की जेब में 2,250 करोड़ रुपये अधिक गए. हिंदुस्तान जिंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में 6,972 करोड़ रुपये के अंतिरिम डिविडेंड का भुगतान किया है. इसमें वेदांता के हिस्से में 4,526 करोड़ रुपये का डिविडेंड आया. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यह डिविडेंड अभी नहीं दिया गया, तो डीलिस्टिंग के बाद मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज के एमडी श्रीराम सुब्रमण्यन ने कहा, कंपनी बोर्ड को डिविडेंड वितरण नीति का सख्ती से पालन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरधारकों को डिविडेंड मिले. यदि ऐसा नहीं होता, तो पॉलिसी पर भरोसे पर सवाल उठते हैं। सेबी के लिस्टिंग नियमों के अनुसार, टॉप 500 सूचीबद्ध कंपनियों की अपनी डिविडेंड वितरण नीति होना अनिवार्य है. वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है और इसके पास 37,914 करोड़ रुपये की नकदी और ठोस निवेश है।

सार्वजनिक उपक्रमों का उत्पादन 90 प्रतिशत पर पहुंचा

नई दिल्ली, (नईदिल्ली) भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कोविड-19 महामारी के समय में सार्वजनिक उद्योमों के प्रदर्शन पर बुधवार को एक सार पुस्तिका लॉन्च की। सार्वजनिक उपक्रमों को देश का गौरव बताते हुये श्री जावडेकर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी इन कंपनियों ने बिजली, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसे जरूरी उत्पादों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की। अनलॉक के साथ अब सार्वजनिक कंपनियों का उत्पादन सामान्य दिनों की तुलना में 90 प्रतिशत पर पहुँच चुका है। भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ स्वावलंबी, पुनरुत्थानशील, लचीले भारत का निर्माण - कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक उद्यमों का योगदान नामक यह सार पुस्तिका जारी करते हुये श्री जावडेकर ने कहा सार्वजनिक उपक्रम देश का गौरव हैं। महामारी के दौरान उन्होंने प्रशंसनीय काम किया है। बिजली की आपूर्ति 99 प्रतिशत रही और कहीं कोई पावर फेल्योर नहीं हुआ। तेल विपणन कंपनियों ने 24 हजार रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरों, 71 हजार पेट्रोल पंपों और 6,500 मिट्टी तेल डीलरों के जरिये लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते रहे। कुल 71 करोड़ रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति की गई जिसमें 21 करोड़ सिलिंडर उज्जवला योजना के लाभार्थियों को दी गई। उन्होंने बताया कि माल ढुलाई और परिवहन लगभग शत-प्रतिशत बना रहा। इस दौरान 3.3 करोड़ टन खाद्य पदार्थों की ढुलाई की गई। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रबंधित अस्पतालों में 11 हजार बिस्तर कोविड-19 के मरीजों के लिए उपलब्ध कराए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की करीब 250 कंपनियों का टर्नओवर 25 लाख करोड़ रुपये का और मुनाफ 1.75 लाख करोड़ रुपये है। लाभांश, ब्याज, कर और जीएसटी के माध्यम से ये कंपनियां 3.62 हजार करोड़ रुपये सरकार को देती हैं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 3,873 करोड़ रुपये सामाजिक कार्य पर खर्च करती हैं।

आज से बदल जाएंगे आम लोगों से जुड़े ये नियम

नई दिल्ली | एजेंसी।

कोरोना काल में सरकार ने कई तरह की रियायतें दीं गई जिनकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। वहीं, एक अक्तूबर से बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से किन नियमों के जरिए आपको फायदा होगा और किससे नुकसान उठाना उड़ेगा।

एसबीआई कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने जा रहा है। इससे ग्राहकों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक भी यही फैसला लागू करेंगे।

एसबीआई मेट्रो शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5000 से घटाकर तीन हजार करने जा रहा। पूर्ण शहरी इलाके में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम शुल्क देना होगा। 75 फीसदी से कम राशि होने पर पहले जहां 80 रुपए व जीएसटी लगता था वहीं, अब सिर्फ 15 रुपए व जीएसटी देना होगा। 50 से 75 फीसदी राशि कम होने पर 12 रुपए व जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपए

जीएसटी के साथ है। देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। ड्राइविंग के समय डीएल और आरसी को साथ रखने की आवश्यक नहीं होगा। पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा। इन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा। कोरोना काल में अप्रैल से ही गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, जिसकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। यानी हो सकता है कल से मुफ्त गैस सिलेंडर न मिले। जुर्माने के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है। कोरोना काल में इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है, अगर अब नहीं बढ़ी और आपने आयकर रिटर्न नहीं फाइल की तो परेशानी होगी।

अटल पेंशन योजना लेने वाले लोगों को खाते को नियमित कर लेना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे जुर्माना देना पड़ सकता है। जून 2020 तक ऑटो-डेबिट सुविधा बंद कर दी गई थी। खाद्य मंत्रालय ने कोरोना काल में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। आप राशन कार्ड और आधार को लिंक सिर्फ बुधवार तक करा सकते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूती में लौटने तक सोने की मांग में तेजी

नई दिल्ली | एजेंसी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूत सुधार के रास्ते पर लौटने तक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में तेजी जारी रहने का अनुमान है. बाजार आंकड़े उपलब्ध कराने वाली कंपनी रेफिनिटिव ने यह जानकारी दी है. रिफिनिटिव के वरिष्ठ धातु विश्लेषक देबजीत साहा ने मंगलवार को कहा, पूरी दुनिया में केन्द्रीय बैंकों ने कोविड- 19 महामारी के कारण पैदा आर्थिक सुस्ती का मुकाबला करने के लिये अप्रत्याशित रूप से प्रोत्साहन पैकेज जारी किये हैं। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये बैंकों ने ब्याज दरों को या तो एतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंचा दिया गया है या फिर ये शून्य से भी नीचे चली गई हैं उन्होंने कहा कि सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग के तब तक जारी रहने का अनुमान है जब तक कि कम से कम वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत सुधार के रास्ते पर नहीं आ जाती है. रिफिनिटिव प्रमुख (मूल्यवान धातु शोध) कैमरॉन एलेक्जेंडर ने एक वेबिनार के अवसर पर कहा कि पिछले कुछ महीने अप्रत्याशित रहे हैं और कई बाजारों पर

कोविड- 19 का गहरा असर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 का हाजिर मांग पर असर वर्ष के अंत तक धीरे धीरे समापत हो सकता है लेकिन वार्षिक मांग के आंकड़ों पर इसका असर काफी भारी दिखाई दे सकता है. आभूषण की मांग पर गहरा असर पड़ सकता है, इस साल यह 40 प्रतिशत तक नीचे रह सकती है जबकि खुदरा निवेश में 15 प्रतिशत का उछाल आ सकता है. सुरक्षित निवेश को ध्यान में रखते हुये निवेशकों की नजर सोने पर है. उन्होंने कहा, हाल की राहत के बाद, ईटीएफ की मांग वर्ष की समाप्ति तक एक बार फिर से बढ़ने का अनुमान है और यह 2020 में 1,000 टन से अधिक तक पहुंच सकती है।

रिलायंस रिटेल में जनरल अटलांटिक करेगा 3,675 करोड़ रुपये का निवेश

● रिलायंस रिटेल की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप जनरल अटलांटिक का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। सभी भारतीय उपभोक्ताओं और व्यापारियों के हित में हम भारतीय रिटेल ईको-सिस्टम का विकास जारी रखेंगे। रिटेल स्पेस में जनरल अटलांटिक के पास जबरदस्त विशेषज्ञता है और इससे हमें लाभ की उम्मीद है।

मुंबई | एजेंसी।

वैश्विक निवेश फर्म जनरल अटलांटिक 0.84 फीसदी इक्विटी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) में 3,675 करोड़ रूपय का निवेश करेगी। यह रिलायंस रिटेल में तीसरा बड़ा निवेश है। बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने इस निवेश की घोषणा की। सौदे में रिलायंस रिटेल की प्री-मनी इक्विटी को 4.285 लाख करोड़ रुपये आंका गया। साल की शुरुआत में जनरल अटलांटिक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 6,598.38 करोड़ का निवेश किया था। यह

जनरल अटलांटिक का रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी में दूसरा निवेश है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर मे फैले 12 हजार से ज्यादा स्टोर्स में सालाना करीब 64 करोड़ खरीददार आते हैं। कंपनी खुदरा वैश्विक और घरेलू कंपनियों, छोटे उद्योगों, खुदरा व्यापारियों और किसानों का एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहती है, जिससे उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर सेवा प्रदान की जा सके और लाखों रोजगार पैदा किए जा सकें। रिलायंस रिटेल ने अपनी नई वाणिज्य रणनीति के तहत छोटे और असंगठित व्यापारियों का डिजिटलीकरण शुरू किया है। कंपनी का लक्ष्य 2 करोड़ व्यापारियों को इस नेटवर्क से जोड़ना है। यह नेटवर्क व्यापारियों को बेहतर टेक्नॉलोजी के साथ ग्राहकों को बेहतर मूल्य पर सेवाएं देने में सक्षम बनाएगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि वह काफी खुश हैं कि जनरल अटलांटिक के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। हम व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और अंततः भारतीय रिटेल की तस्वीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं। रिलायंस रिटेल की तरह, जनरल अटलांटिक भी प्रगति और विकास के लिए डिजिटल क्षमता में विश्वास करती है। जनरल अटलांटिक की विशेषज्ञता और भारत में निवेश के दो दशकों के उसके अनुभव का लाभ उठाने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि हम देश में रिटेल की सूरत बदलने के लिए नया कॉमर्स प्लेटफार्म विकसित कर रहे हैं।

जनरल अटलांटिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिल फोर्ड ने कहा कि जनरल अटलांटिक देश के रिटेल क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की मुकेश अंबानी के मिशन का समर्थन करती है। जनरल अटलांटिक टेक्नॉलोजी की ताकत में रिलायंस इंडस्ट्रीज की धारणा में भी गहरा विश्वास रखती है। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से रिलायंस टीम के साथ भागीदारी करने पर सम्मानित महसूस कर रहे है।

लिखिता इंफा का आईपीओ दूसरे दिन 1.32 गुना तक सब्सक्राइब

नई दिल्ली, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का 61.20 करोड़ रुपये का आईपीओ दूसरे दिन के मध्य तक 1.32 गुना तक सब्सक्राइब किया गया. कंपनी का इश्यू सोमवार (29 सितंबर) को खुला और इसे बुधवार (1 अक्टूबर) तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। इस इश्यू को पहले ही दिन 100 फीसदी तक का सब्सक्रिप्शन मिल गया था. कंपनी ने बिक्री के लिए 51,00,000 शेयर पेश किए हैं, जिसमें से 69,25,500 शेयरों के लिए बोली लगाई जा चुकी है. इस आधार पर इश्यू को 1.32 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला है। हैदराबाद की इस ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा कंपनी के इश्यू के लिए 117-120 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 की प्रति शेयर आय की तुलना में 12 गुना के भाव पर पर उपलब्ध है। निवेशक को कम से कम 125 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगानी होगी. इसके गुणक में ज्यादा निवेश के लिए बोली लगाई जा सकती है. इस तरह इश्यू में निवेश करने के लिए कम से कम 14,625 रुपये खर्च करने होंगे। इस साल मार्च में खत्म वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 15.83 फीसदी बढ़कर 162.79 करोड़ रुपये रहा।

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक
स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।
संपादक- कंचन सोलंकी
TITLE CODE- UPHIN48974
Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com

नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।